



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2009/श्रावण 14, 1931

No. 257]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2009/SRAVANA 14, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2009

विषय : चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित "बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर" के आयातों के बारे में पाटनरोधी जाँच-प्रारंभिक जाँच परिणाम।

सं. 14/6/2009-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम (जिसे आगे पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :—

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत बरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ मेन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएमएफआईआई) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जन. गण. तथा इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित "बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था।
- (ii) आवेदन की प्रारंभिक जाँच से कुछेक कमियों का पता चला जिन्हें आवेदक ने बाद में सुधार दिया था। अतः आवेदन को समुचित ढंग से प्रलेखित माना गया था।
- (iii) जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में जाँच शुरू करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार जाँच शुरुआत की कार्रवाई से पूर्व पाटन के आरोप की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।
- (iv) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए 19 मार्च, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार तत्परत ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्योरे आवेदक ने उपलब्ध करार थे) और उद्योग एग्रेसिविजनों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

vi. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के तत्परत ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भी भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी ।

vii. पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्योरों की व्यवस्था करने के लिए कॉमिश्निक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था । डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया गया था और उसकी तुलना इंडोनेशिया के प्रतिवादियों से प्राप्त सूचना के साथ की गई थी । यह पाया गया था कि प्रतिवादियों ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों की उष्णतर मात्रा सूचित की है । इस प्रकार आयात के आंकड़ों का संकलन कर उनका मिलान डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और इंडोनेशिया के प्रतिवादियों से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया था ।

viii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों तथा भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अनोपनीय स्वांतरण की प्रति उपलब्ध कराई । अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पार्टियों को भी आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई थी ।

ix. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना मांगने के लिए प्रश्नावलियां भेजी:

- पी.टी. साउथ पेट्रिकिफिक बिस्कोस
- हेबाई जिगाओ केमिकल फाइबर कं. लि.
- कुन्शान हेंगशेंग केमिकल फाइबर कं.
- जिबो हुआलॉग केमिकल फाइबर कं. लि.
- हुआई केमिकल फाइबर ग्रुप लि.,
- गाओमी सिस्वर होंक केमिकल फाइबर कं. लि.
- सतेरी (जियांगसी) केमिकल फाइबर कं. लि.
- फुलीदा ग्रुप होल्डिंग कं. लि.
- मनासी अजोयांग टेक्नीकल कं. लि.
- यीबिन ग्रेस ग्रुप कंपनी लि.

पी.टी. इंडो भारत रेयान

x. जांच शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में इंडोनेशिया के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया है:

- मै. पी.टी. इंडो भारत रेयान
- मै. पी.टी. साउथ पैसिफिक विस्कोस

xi. चीन जन.गण. के किसी उत्पादक तथा निर्यातक ने न तो उत्तर दिया है और न ही कोई संगत सूचना दायर की है और कोई अनुरोध भी नहीं किया है।

xii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

<ul style="list-style-type: none"> ● पल्लव टेक्सटाइल्स ● चेरन स्पिन टेक्स (आई) लि., ● पल्लीपलायम स्पिनर्स, ● श्री चेरन सिन.इंडिया लि. ● केसर मल्टीयार्न मिल लि. ● सुन्दरराजा मिल्स लि., ● गिन्नी फिलामेंट्स लि., ● पीकेपीएन स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि., ● अडानी एन्टरप्राइजेज लि. ● राजाफलायम मिल्स लि. ● सतलेट इंडस. लि. ● पल्लव टेक्सटाइल्स ● जेनिथ स्पिनर्स ● चेरन स्पिनटेक्स (आई) लि., ● पी वी टेक्सटाइल्स, ● बिरला टेक्सटाइल्स मिल्स, ● एजीटी मिल्स. प्रा.लि. ● मोथी स्पिनर्स लि., ● ओरिएन्ट सिन्टैक्स, ● एसएमपी टेक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लि. 	<ul style="list-style-type: none"> ● आरएसडब्ल्यूएम लि. ● रिलायंस कैमोटैक्स इंड लि., ● श्री राजस्थान सिन्टैक्स ● पल्लीपलायम स्पिनर्स, ● राजगुरु स्पिनिंग मिल्स, ● दीपक स्पिनर्स लि., ● अंकुर उद्योग, चोला स्पि. मिल्स, ● पीकेपीएन स्पि. मिल्स (प्रा.) लि. ● जीमाटेक्स इंड प्रा. लि. ● श्री भगीरथ टेक्सटाइल्स लि., ● सुन्दरराजा मिल्स लि., ● सूर्यलता स्पि.मिल्स ● जिलेन्डर्स अरबुतनाट एंड कं. ● विक्टरी स्पि. मिल्स ● अरुण कुमार स्पि. मिल्स प्रा., ● आरएसडब्ल्यूएम लि. ● चेरन स्पि. लि. ● श्री भरनी स्पि. ● सुतलेट इंडस. लि. ● राजगुरु स्पि. मिल्स ● पल्लव टेक्सटाइल्स
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ● केशर मल्टीयार्न मिल लि. ● केशर मल्टीयार्न मिल लि. ● सरमंगल सिंथेटिक्स, ● श्री राजस्थान सिन्टेक्स लि., ● महाराजा सतायम इंड लि. ● एसएमपी टेक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लि. ● नाहर स्पिनिंग ● चोला स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि., ● पीकेपीएन स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. ● श्री कार्तिकेय स्पि. एंड वीव. मिल्स, ● केआरवी स्पि. मिल्स प्रा.लि. ● वेलाताल स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि., ● श्री दीनाकर फैब्रिक्स ● आरकाट टेक्सटाइल मिल लि. ● वल्ली स्पिनिंग मिल्स ● बांसवाड़ा सिनटेक्स लि. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिद्धार्थ एक्सपोर्ट प्रा. लि. ● चालीस्वरर स्पि. मिल्स, ● सुन्दरराजा मिल्स लि., ● श्री करपागम्बल मिल्स ● श्री हरी प्रसास टेक्सटाइल्स ● वर्धमान टेक्सटाइल्स लि. ● श्री नल्लाथल स्पि. मिल्स ● मोषी स्पि. लि., ● सुपर टेक्स मिल्स इंडिया प्रा.लि., ● जीवीएस स्पि., ● रू स्पि. मिल्स ● सर्राफ यार्न प्रा.लि. ● संगम स्पि. लि. ● चेनाब टेक्सटाइल्स मिल्स , ● स्वेनटेक्स इंड लि. ● सूर्यलता स्पि. मिल्स
---	---

xiii. इसके उत्तर में निम्नलिखित ने उत्तर दिया है:

- इंडियन स्पिनर्स एसो.-मुंबई
- श्री राजस्थान सिनटेक्स लि.
- सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स लि.
- स्पेनटेक्स इंड लि.
- पी वी टेक्सटाइल्स लि.
- श्री चेरन सिंथेटिक इंडिया लि.
- पल्लव टेक्सटाइल लि.
- आरएसडब्ल्यूएम लि.
- पल्लीपलायम स्पिनर्स प्रा. लि.

xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा;

xv. आवेदक द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और उसे बनाने तथा बेचने

की लागत निकाली गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- xvi. यह जांच 1 जुलाई, 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, अप्रैल, 08-जून 08 की अवधि और जांच अवधि शामिल थी।
- xvii. *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान घरेलू वस्तु

3. विचाराधीन उत्पाद "बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)" है। सीमाशुल्क टैरिफ के अंतर्गत विस्कोस स्टेपल फाइबर को "पिनाई/धुनाई न किये गए विस्कोस रेयन स्टेपल फाइबर" के रूप में वर्णित है और इसे समान बाजारों में "रेयन फाइबर" के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 5504.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

3.1 विस्कोस स्टेपल फाइबर सर्वप्रथम मानव निर्मित फाइबर था और अन्य मानव निर्मित फाइबरों के विपरीत यह सिंथेटिक फाइबर नहीं है। इसका निर्माण वेट स्पिनिंग प्रौद्योगिकी के जरिए किया जाता है और कास्ट की लुगदी, जो कास्ट को विभिन्न रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजार कर सतत धारणीय प्राकृतिक संसाधन अर्थात् कास्ट से निष्कर्षित अनिवार्य सेल्युलोज है, से निर्मित एक री-जेनेरेटेड सेल्युलोज फाइबर है। सेल्युलोलिसिक आधार के कारण विस्कोस स्टेपल फाइबर के गुणधर्म थर्मोप्लास्टिक, पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक फाइबर यथा: नाइलोन या पालिएस्टर के गुणधर्मों से भिन्न प्राकृतिक सेल्युलोलिसिक फाइबर के गुणधर्मों से मिलते-जुलते होते हैं। इसके अलावा, इसमें इंजीनियर्ड विनिर्देशन तथा समानता का अंतर्निहित लाभ होता है।

3.2 विस्कोस स्टेपल फाइबर ने उत्कृष्ट ड्रैप, सुखद एहसास के साथ रेशम जैसा सौन्दर्यबोध होता है और उसमें बेहतरीन रंग होते हैं। इससे निर्मित फैब्रिक्स आद्रता अवशोषी (सूत से भी अधिक), सगंध, पहनने में आरामदायक होते हैं और इन्हें आसानी से विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। इनमें सीधे खिंचाव नहीं आता है और ये पिलरोधी होते हैं।

3.3 वीएसएफ की मुक्त क्षमता उसकी लोचशीलता और समस्त अन्य वस्त्र फाइबरों के साथ आसानी से मिश्रण क्षमता है जिससे सौन्दर्य, कोमलता, अवशोषकता आती है जिससे इस प्रकार के मिश्रणों के कारण निर्मित फैब्रिक आरामदायक हो जाते हैं। बांस के फाइबर, जो एक प्रकार का विस्कोस स्टेपल फाइबर है, को इस जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। जांच शुरुआत की अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों से विशिष्ट तौर पर यह अनुरोध किया था कि

वे बांस के फाइबर को छोड़ने के बारे में अपने अनुरोध करें। किसी भी विवाद पर पार्टी ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया था।

3.4 समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उपबंध है :

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु से है जो भारत में कस्टम के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचधीन वस्तु से अपेक्षित मिलती-जुलती विशेषताएं हो

3.5 आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। इस संबंध में किसी भी विरोधी विवाद पर पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

3.6 उपलब्ध सूचना से इस चरण पर यह पता नहीं चलता है कि घरेलू समान वस्तु तथा आयातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

4. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नानुसार है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित फाटित वस्तु के निर्वर्तकों या अन्तर्गतों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।

4.1 यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ ग्रेन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसने क्षति एवं लायत सूचना उपलब्ध कराई है। आवेदक ने दावा किया है कि भारत में समान वस्तु का दूसरा कोई उत्पादक नहीं है। विवाद में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. का उत्पादन घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है।

4.2 मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में संबद्ध कंपनियां हैं जो इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करती हैं अर्थात् बिरला जिंकवाई काइवर्त कं. लि., चीन तथा पीटी

इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया। चीन स्थित संबद्ध कंपनी ने भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है जबकि इंडोनेशियाई कंपनी ने भारत को अल्प मात्रा में निर्यात किया है जो आयातों के 3% से कम बनता है और यह भारतीय उत्पादन के संदर्भ में नगण्य है। चूंकि इन आयातों की मात्रा काफी कम है, अतः प्राधिकारी यह मानना उचित समझते हैं कि आवेदक को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखना अपेक्षित नहीं है। किसी भी विरोधी हितबद्ध पार्टी ने इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। मै. पी.टी. इंडो भारत रेयन-इंडोनेशिया ने भी भेजी गई प्रश्नावली का विस्तृत उत्तर दायर किया है।

4.3 इस प्रकार प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि इस आवेदन में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा, मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जा रहा है।

घ. अन्य मुद्दे

5. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- उन्होंने गौण स्रोत से घरेलू उद्योग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आपत्ति व्यक्त की है। वे यह मानते हैं कि अधिकारिक आंकड़े प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवेदक की जिम्मेवारी थी। चूंकि आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़े अधिकारिक नहीं हैं, इसलिए आवेदक का निष्कर्ष गलत है।
- मंदी की स्थितियों के कारण विश्व भर में फैब्रिक की खपत में भारी कमी आई है और इसका न केवल फैब्रिक की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है, अपितु विस्कोस स्टेपल फाइबर सहित यार्न और फाइबर भी प्रभावित हुए हैं।
- आवेदक ने एनएजीडी संयंत्र में जल की कमी की अवधि को छोड़कर अपनी पूर्ण क्षमता पर हमेशा प्रचालन किया है परंतु मंदी के कारण वर्ष 2008-09 में इसने अपना खारच संयंत्र बंद कर दिया और क्षमता उपयोग पर भी प्रभाव पड़ा।
- जांच अवधि के दौरान आयातों की औसत सीआईएफ कीमत 2007-08 की औसत सीआईएफ कीमत से अधिक है।
- घरेलू उद्योग की मूलभूत समस्या प्रवृत्तियों में परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना क्षमता का सतत विस्तार करना रही है।
- आवेदक के पास व्यापक संसाधन और विश्वव्यापी संविदाएं हैं और उसे कताई उद्योग की मदद करने में अग्रणी रहना चाहिए।
- आवेदक भारत में संबद्ध उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ग्रासिम एवं उनके कंपनी समूह के पक्ष में एकाधिकारवादी स्थिति उत्पन्न होगी जिनके पास थाइलैंड सहित अन्य देशों में भारी वीएसएफ क्षमताएं हैं।

5.1 पीटी साउथ पैसिफिक मिरकोस के अनुरोध

- पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण के विश्लेषण हेतु 6 माह की जांच अवधि काफी कम है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई व्यापार सूचना में भी यह अधिदेश है कि जांच अवधि सामान्यतः 12 माह की होनी चाहिए।
- संबंधित उत्पाद का अनन्य सीमाशुल्क कोड है; इसलिए आयातों के आधार के रूप में गौण स्रोत पर विचार करना न्यायोचित नहीं है।
- डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में गौण स्रोतों की तुलना में काफी अधिक मात्रा दर्शायी गई है और उसकी कीमत भी अधिक है।
- डीजीसीआईएंडएस के अनुसार अन्य देशों से आयात हुए हैं लेकिन आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से इतर देशों से कोई आयात नहीं हुआ है।

5.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

- जांच अवधि - याचिका में जांच अवधि के रूप में 6 माह पर विचार करने के विशिष्ट कारण दिए गए हैं। ऐसा हितबद्ध पार्टियों के इस तर्क के बावजूद हुआ है कि 6 माह की जांच अवधि अनुमत्य नहीं है। यद्यपि व्यापार सूचना में "सामान्य" शब्द का उपयोग हुआ है न कि "सदैव" शब्द का। एचएस के मामले में सेस्टेट के निर्णय के संगत उद्धरण संलग्न किए गए हैं जिसमें न्यायाधिकरण ने स्पष्ट तौर पर यह निर्णय दिया है कि जांच अवधि के रूप में 6 माह पर विचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जहां तक 6 माह की अवधि को चुनने का संबंध है, याचिका में इसी बात का उल्लेख है। इस सीमा तक तर्क वस्तुतः सही है।
- याचिका में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि सूचना टिप्स से प्राप्त की गई है। ऐसा मामला होने के कारण यह तर्क निराधार है कि स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है। जहां तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के उपयोग का संबंध है, इन्हें इस कारण नहीं अपनाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का अनन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पार्टियों में कुछ गलतफहमी है कि विचाराधीन उत्पाद का अनन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण है। इसके अलावा, सौदा-दर-सौदा आंकड़े निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने के बाद ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जहां तक याचिका में उल्लिखित आंकड़ों के साथ डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का संबंध है, चूंकि उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार का वीएसएफ शामिल नहीं है, इसलिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के साथ कोई तुलना भ्रामक होगी।
- कंपनी के खारच संयंत्र में पूर्व में दो उत्पादन लाइनें थीं। दो और लाइनें जोड़ी गई थीं जिन्होंने उत्पादन मार्च-अप्रैल, 2008 की अवधि में शुरू किया था। क्षमता में यह वृद्धि ग्राहकों द्वारा प्रदत्त बाजार पूरक सूचना के आधार पर की गई थी। वस्तुतः कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त इस आशय की पूरक सूचना पर ही क्षमता विस्तार की योजना बनाई थी।

कि उत्पाद की मांग अच्छी है। तथापि, पाटन एवं प्रतिकूल बाजारी स्थिति के कारण जांच अवधि में इन दोनों लाइनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका।

प्राधिकारी द्वारा जांच

5.3 प्राधिकारी ने जांच अवधि के बारे में हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और उनका यह मत है कि वर्तमान मामले में चुनी गई जांच अवधि का चुनाव मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए उचित ढंग से किया गया है जिसमें इस विषय पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े भी शामिल हैं। इसके अलावा, जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि लेने के निर्णय को माननीय न्यायाधिकरण ने भी विरचाऊ लेबोरेटरीज लि. बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में भी बरकरार रखा है।

5.3.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर है। विचाराधीन उत्पाद के लिए सीमाशुल्क वर्गीकरण में बांस के फाइबर को अलग नहीं रखा गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त सूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें विचाराधीन उत्पाद से भिन्न उत्पाद के आयात शामिल हो सकते हैं। घरेलू उद्योग ने टिप्स द्वारा प्रदत्त सूचना प्रस्तुत की है जिसे जांच की शुरुआत के समय स्वीकार किया गया था।

5.3.2 घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5504 9090 के अंतर्गत भारी मात्रा में आयात होने की सूचना दी गई है। प्राधिकारी ने सीमाशुल्क वर्गीकरण सं. 55041000 तथा 55049090 के लिए आयात की सूचना हेतु डीजीसीआईएंडएस के कार्यालय से अनुरोध किया था जिसे प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया गया था। तदनुसार संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा का निर्धारण किया गया है। आवेदक द्वारा टिप्स के आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार दावा किए गए आयातों की तुलना से निम्नानुसार पता चलता है:

	टिप्स आंकड़े		डीजीसीआईएंडएस आंकड़े	
	मात्रा किग्रा.	रु./किग्रा.	मात्रा किग्रा.	रु./किग्रा.
चीन जन.गण.	907252	96.03	1023971	94.13
इंडोनेशिया	4533741	98.44	4689364	98.47

5.3.4 रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों को छोड़कर किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है। डीजीसीआईएंडएस और टिप्स के अनुसार मात्रा एवं कीमत मोटे तौर पर तुलनीय है।

ड. पाटन मार्जिन

6. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया तथा चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात निर्यातकों तथा उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी । इस पर इंडोनेशिया के निम्नलिखित केवल दो उत्पादकों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

- मै. पी टी इंडो भारत रेयन
- मै. पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस

इंडोनेशिया के सहयोगी निर्यातकों तथा उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

मै. पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस

6.1 मै. पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस, इंडोनेशिया ने उत्तर दिया है और सूचना उपलब्ध कराई है । प्रस्तुत उत्तर में कुछ कमियां पाई गई थीं और स्पष्टीकरण मांगे गए थे । कंपनी ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्री तथा परिशिष्ट-2 में भारत को किए गए निर्यातों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है । कंपनी ने परिशिष्ट-5, 6 से 8 में उत्पादन लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है । आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि कंपनी की भारित औसत घरेलू बिक्री कीमत भारित औसत घरेलू उत्पादन लागत से कम है । प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदेवार घरेलू बिक्री के साथ की गई है और यह पाया गया है कि ***% घरेलू बिक्रियां लाभ में की गई हैं । इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों के आधार पर किया गया है । कमीशन, बैंक प्रभारों एवं ऋण लागत के लिए दावा किए गए समायोजनों की अंतिम अनुमति दी गई है जो आगे और जांच तथा मौके पर सत्यापन के अधीन है । इस प्रकार सामान्य मूल्य *** अम. डॉ. प्रति किग्रा. बनता है ।

मै. पी.टी. इंडो भारत रेयन

6.2 इंडोनेशिया की मै. पी.टी. इंडो भारत रेयन ने उत्तर दिया है और निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से सूचना उपलब्ध कराई है । प्रतिवादी ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है । प्रतिवादी ने परिशिष्ट 5 से 9 में उत्पादन लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी ने अपनी घरेलू बिक्रियों पर समग्र आधार पर लाभ कमाया है । प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदेवार घरेलू बिक्री के साथ की गई है और यह पाया गया है कि ***% घरेलू बिक्रियां लाभ में की गई हैं । इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों के आधार पर किया गया है । कमीशन, बैंक प्रभारों एवं ऋण लागत के लिए दावा किए गए समायोजनों की अंतिम अनुमति दी गई है जो आगे और जांच तथा मौके पर सत्यापन के अधीन है । इस प्रकार सामान्य मूल्य *** अम. डॉ. प्रति किग्रा. बनता है ।

कार्यप्रणाली: समग्र देश के लिए एक सामान्य मूल्य

6.3 इंडोनेशिया के लिए समग्र रूप से सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है । इस प्रयोजनार्थ ऊपर की गई चर्चा के अनुसार सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य तथा

घरेलू बाजार में उनकी लाभ योग्य बिक्रियों के भार पर विचार किया गया है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

नाम	मै. पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस	मै. पी टी इंडो भारत रेयन	भारित औसत
सामान्य मूल्य	***	***	***
लाभ योग्य घरेलू बिक्री किग्रा. में	***	***	***

घ निर्यात कीमत

मै. पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस

7.1 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु अनंतिम रूप से भरोसा किया जा रहा है जो आगे और जांच तथा मौके पर सत्यापन के अधीन है। प्रतिवादी ने समुद्री परिवहन, ऋण लागत एवं बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है जिन्हें आगे और जांच तथा मौके पर सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ निर्यातक के लिए निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. निर्धारित की है।

मै. पी टी इंडो भारत रेयन

7.2 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु अनंतिम रूप से भरोसा किया जा रहा है जो आगे और जांच तथा मौके पर सत्यापन के अधीन है। प्रतिवादी ने अंतरराष्ट्रीय भाड़े, अंतरदेशीय परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय बीमा, आंतरिक बीमा एवं अन्य व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया है जिन्हें आगे और जांच तथा मौके पर सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ निर्यातक के लिए निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. निर्धारित की है।

इंडोनेशिया के असहयोगी निर्यातकों तथा उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण

7.3 इंडोनेशिया के किसी अन्य निर्यातक तथा उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

7.4 प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के ज्ञात निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी कि निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना उपलब्ध कराई जाए। तथापि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से प्रश्नावलियों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

7.5 नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उपबंधित है कि:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में सम्मान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी दिव्यसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विचार के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

7.6 प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में भारत तथा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है बशर्ते निर्यातक देश और अलग-अलग निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी जांचों के अनुसार इस अनुमान का खंडन किया गया हो।

7.7 पाटनरोधी निर्यातकों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण. के निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मामलों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उनके विपरीत सिद्ध करते हैं। चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार विषयक प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- (क) कच्ची सामग्रियों कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, निविष्टि और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों

का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

7.8 प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरूआत संबंधी सूचना के बाद चीन के किसी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन नहीं किया है । जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में ही प्राधिकारी ने यह संकेत दिया था कि आवेदक ने उचित प्रतिनिधि देश के रूप में इंडोनेशिया का सुझाव दिया है । हितबद्ध पार्टियों ने इस संबंध में अनुरोध करने का निवेदन किया था । तथापि, चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है और इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है । अतः प्राधिकारी ने इंडोनेशिया पर चीन जन.गण. के लिए उचित प्रतिनिधि देश के रूप में विचार किया और इंडोनेशिया में सामान्य मूल्य *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित किया । प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए भी सामान्य मूल्य का परिकलन किया परंतु यह पाया कि उचित प्रतिनिधि देश के रूप में इंडोनेशिया के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित सामान्य मूल्य से कम है और इसीलिए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ उचित प्रतिनिधि देश के रूप में इंडोनेशिया के आधार पर किया है ।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

8. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने गौण स्रोतों के अनुसार सौदेवार सूचना प्रस्तुत की है । बाद में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से आयात के आंकड़े प्राप्त किये । अतः प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन.गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है । निर्यात कीमत में समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशी भाड़े, पत्तन व्यय तथा बैंक कमीशन को रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार समायोजित किया गया है । इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. बनती है ।

छ. पाटन मार्जिन का निर्धारण

9. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
इंडोनेशिया				
मै. पी टी साउथ पेसेफिक विस्कोस	***	***	***	6.30%
मै. पी टी इंडो भारत रेयन	***	***	***	11.26%
ऊपर उल्लिखित दोनों कंपनियों को छोड़कर अन्य	***	***	***	54.91%
चीन जन.गण.	***	***	***	
समस्त निर्यातक तथा उत्पादक	***	***	***	14.16%

9.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. और इंडोनेशिया से पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ज. क्षति**मै. पी.टी. साउथ पेसेफिक विस्कोस-इंडोनेशिया के अनुसार**

10. मै. पी.टी. साउथ पेसेफिक विस्कोस ने ये तर्क दिए हैं कि:

- मांग में कमी आई है जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है; अतः आरोपित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमत संशोधन का संबद्ध देशों से हुए आरोपित पाटित आयातों से कोई लेना-देना नहीं है।
- घरेलू उद्योग की कम लाभप्रदता मुख्यतः संबंधित निविष्टि लागत, कम मात्रा एवं कम मार्जिन के कारण रही है। मूल्य ह्रास कीमत तथा ब्याज काफी अधिक प्रतीत होता है जो घरेलू उद्योग की कम लाभप्रदता के कारण हो सकते हैं।
- सीमित परिदृश्य के बावजूद घरेलू उद्योग ने मार्च, 2008 में अपनी क्षमता में विस्तार किया। किसी औद्योगिक इकाई के लिए प्रचालन की शुरुआत में ही क्षमता का वही स्तर प्राप्त करना संभव नहीं होता है।

- बिक्री मात्रा में गिरावट आई जिसकी वजह आरोपित पाटन नहीं थी।
- घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन तथा वैश्विक मदी के बावजूद परियोजना का विस्तार जारी है। अतः जहां तक निवेश एवं विस्तार कार्यक्रम का संबंध है, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- किसी वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- घरेलू उद्योग एक ऐसी कीमत नीति का पालन करता है जिसके जरिए वह पर्याप्त रिबेट प्रदान करता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में कोई दावा स्वीकार करने से पूर्व कीमत नीति का विश्लेषण करना चाहिए।
- इंडोनेशिया से अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए जाते हैं।
- आरोपित पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- याचिकाकर्ता द्वारा मांग, निर्यात आधार पर घरेलू बाजार में भारी मात्रा में बिक्री की जा रही है जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक छूट प्रदान की जा रही है। ये बिक्रियां घरेलू बिक्रियां नहीं हैं और इन्हें वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्री से अलग रखा जाना चाहिए।
- कंपनी द्वारा घरेलू बाजार में होने वाली बिक्री में भारी छूट दी जा रही है जो याचिकाकर्ताओं की कीमत सूची से ही स्पष्ट हो जाती है। घरेलू उद्योग को क्षति यदि कोई हो, उसकी खुद की कीमत नीति के कारण हुई है न कि आरोपित पाटन के कारण।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

10.1 घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि:

- अधिकांश मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2007-08 तक सुधार हो रहा था तथापि, घरेलू बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह आतद के संबंध में निष्पादन में गिरावट आई। अधिकांश महत्वपूर्ण मापदंडों में से कुछ के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच अवधि के दौरान नाटकीय ढंग से गिरावट आनी शुरू हुई और जांच अवधि की समाप्ति पर स्थिति ज्यादा खराब हो गई।

- विदेशी उत्पादकों के पास भारी अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ-साथ वर्तमान कीमतों की पेशकशों से निष्पादन में और अधिक गिरावट आने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। घरेलू उद्योग को पाटन के कारण नुकसान हुआ है।
- पाटित आयातों की वृद्धि दर काफी अधिक है जिससे अत्यधिक मात्रा में आयात होने की संभावना का पता चलता है ;
- कीमत में अत्यधिक अंतर और आयातों में परिणामी संभावित वृद्धि का घरेलू कीमतों पर भारी कीमत ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है ;
- विदेशी उत्पादकों और भारी उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कटौती की जा रही है। संबद्ध उत्पादकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है जिससे भारतीय बाजारों को पर्याप्त संवर्धित पाटित निर्यात होने की संभावना का पता चलता है जिसकी वजह किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने में अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता है।
- विदेशी उत्पादकों द्वारा की जा रही वर्तमान पेशकशों का तात्पर्य कीमत में अभूतपूर्व कमी से है। कीमत में ये कमियां उनके पास उपलब्ध भारी बेशी मात्रा का परिणाम है। यदि घरेलू उद्योग चीन के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कीमतों की बराबरी करता है तो उसे भारी वित्तीय घाटा होगा। यदि घरेलू उद्योग कीमत में कमी नहीं करता है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि बिक्री में कमी के रूप में भारी उथल-पुथल होगी, उसके बाद उत्पादन में कमी आएगी-उत्पादन लागत में वृद्धि होगी-वित्तीय घाटा बढ़ेगा।
- कीमत में संशोधन तथा कमी-कीमत नीति से स्पष्टतया यह सिद्ध होता है कि कंपनी आयातों की पहुंच कीमत के आधार पर ही अपनी कीमत तय करती है। जहां तक वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों के पत्र का संबंध है, वर्तमान मामले में जांच अवधि जुलाई-दिसंबर, 08 की है (न कि 2007-08 की) वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देना निराधार है।
- लाभप्रदता - हितबद्ध पार्टियों ने स्वीकार किया है कि लाभप्रदता में कमी "संवर्धनशील निविष्टि लागत", "कम मात्रा" तथा "न्यून मार्जिन" के कारण आई है - ये सभी पाटित आयातों से संबंधित हैं। जहां संवर्धनशील निविष्टि लागत को वहन करने की अक्षमता से प्रतिकूल कीमत प्रभाव का पता चलता है वहीं न्यून मार्जिन आयातों के कारण हुए कीमत ह्रास का एक अन्य प्रदर्शक है। जहां तक न्यून मात्रा का संबंध है, यद्यपि मांग में गिरावट का बिक्री में कमी के संबंध में पहले ही प्रभाव पड़ चुका है, वहीं संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में आगे और इजाफा किया है। जहां तक उच्चतर ब्याज और अत्यधिक कीमत ह्रास का संबंध है, एनबीआर के मामले में सेस्टेट के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि घरेलू उद्योग को उसकी मौजूदगी के संबंध में देखा जाना चाहिए न कि किसी आदर्श स्थितियों में। वस्तुतः वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट में निविष्टि लागत में वृद्धि और वीएसएफ की कीमत में कमी

आने का स्पष्ट उल्लेख है। कंपनी की कीमत नीति को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वीएसएफ की कीमत में कमी आयात कीमत में कमी के कारण आई है। ति 2 तथा ति 3 एफ। 2008-09 के प्रदर्शनों में ग्राहकों पर लागत में वृद्धि डालने के बारे में कंपनी की अक्षमता का स्पष्ट तौर पर पता चलता है।

- क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग- क्षमता विस्तार मध्यम एवं दीर्घावधिक व्यापारिक परिदृश्य के आधार पर किए जाते हैं न कि अल्पावधिक, प्रतिकूल व्यापारिक स्थितियों के आधार पर जो पाटन के कारण उत्पन्न हुई हैं। क्षमता विस्तार करने से पूर्व कंपनी ने ग्राहकों से पूरक सूचना प्राप्त की। कंपनी द्वारा क्षमता में वृद्धि, बाजार विश्लेषण/ ग्राहकों से पूरक सूचना पर विचार करते हुए की गई थी। वस्तुतः कंपनी ने ग्राहकों द्वारा सुझाए गए बाजार में विद्यमान मांग की सीमा तक विस्तार नहीं किया है। ऐसा मामला होने के कारण इन उपभोक्ताओं की ओर से अब यह आरोप लगाना गलत है कि कंपनी ने क्षमता से अधिक विस्तार किया है। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विस्तारित क्षमता ने मार्च-अप्रैल 2008 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। कंपनी की लाभप्रदता अप्रैल-जून, 2008 की अवधि में बेहतर रही थी। इस अवधि में ब्याज एवं मूल्य हास का आरोपित प्रभाव भी महसूस किया जाना चाहिए था।
- क्षति का खतरा- विदेशी उत्पादकों के पास वर्तमान क्षमता तथा उनकी घरेलू मांग को किॉर्ड में उपलब्ध प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह देखा जाएगा कि विदेशी उत्पादकों के पास भारी बेसी क्षमताएं हैं। आवेदक ने याचिका में प्रस्ताव की प्रति पूर्व में उपलब्ध कराई है। हर हालत में इन पेशकशों पर प्रस्तुत आर्डर देश में आए हैं। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतिवादी निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की जानी चाहिए।
- अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयात - उनके खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार निर्यातक द्वारा किए गए समस्त आयात अग्रिम लाइसेंस पर नहीं किए गए थे। इसके आधार पर मांग की गणना से इन आयातों को अलग रखना न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ग्राहकों को प्रदान करने वाली रिबेटों के इन आयातों से प्रतिस्पर्धा करता है। इस प्रकार ग्राहक के पास अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातित सामग्री की खरीद करने या घरेलू उद्योग से खरीद करने और निर्यात बाजार में उसकी बिक्री करने का विकल्प होता है। अग्रिम लाइसेंस पर किए गए इन आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग रिबेट प्रदान कर रहा है। अतः (क) अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयातों को मांग तथा बाजार हिस्से के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अलग नहीं रखा जा सकता और (ख) चूंकि ये आयात सामान्यतः अग्रिम लाइसेंस पर किए गए हैं इसलिए कीमत कटौती का निर्धारण करते समय सीमाशुल्क को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आयात की पहुंच कीमत में जोड़े गए परिकल्पित सीमाशुल्क की तुलना घरेलू उद्योग की रिबेटशुदा बिक्री कीमत (जहां सीमाशुल्क के लाभ की क्षतिपूर्ति करने के लिए रिबेट प्रदान किया गया है) के साथ करने पर अत्यंत भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी।

- कारणात्मक संबंध- इन अधिवर्धित तथ्यों कि (क) घरेलू उद्योग एक ऐसी कीमत नीति अपना रहा है जिसमें कीमतों का निर्धारण निर्यात कीमत के आधार पर किया जाता है; और (ख) घरेलू उद्योग बार-बार कीमत में सामान्य कटौती से अधिक कीमत में कटौती करने के लिए बाध्य हुआ है, से ही पाटन एवं प्रति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि हो जाती है।
- घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद की मासिक/वार्षिक वित्तियनक ढंग से काफी अधिक हैं। संबद्ध देशों से हुए निर्यात की कीमत में गिरावट आई है जो कि निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाती है :

निर्यात कीमत अम.डॉ. प्रति किग्रा.

	जुलाई 2008	अगस्त 2008	सितंबर 2008	अक्टूबर 2008	नवंबर 2008	दिसंबर 2008
चीन जन.गम.	2.02	2.02	2.10	2.26	2.09	1.78
इंडोनेशिया	2.28	2.17	2.17	2.18	2.24	2.05

- इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांचोत्तर अवधि में हुए आवक्यों की सीटेंकर सूचना एकत्र की है (नीचे दी गई तालिका)। यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से कीमतों में आगे और गिरावट आई है।

जन-मार्च 09	अमडा./किग्रा.
चीन जन.गम.	1.57
इंडोनेशिया	1.79

- जांचोत्तर अवधि में संबद्ध देशों से निर्यात कीमत में आगे और गिरावट आई है। वस्तुतः ये ऑर्डर जांच अवधि की समाप्ति पर प्रस्तुत किए जाते हैं और इसलिए इन्हें प्रतिवादी निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों में शामिल किया जाना चाहिए।
- वर्ष 2007-08 और जांच अवधि के बीच निर्यात कीमत में वृद्धि-वर्ष 2007-08 की तुलना में जांच अवधि में कच्ची सामग्री की लागत में गतिविधि जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा। इससे निर्यात कीमत में वृद्धि हुई।

रू./किग्रा.	2007-08	जांच अवधि	परिवर्तन
कच्ची सामग्री	***	***	12.6
निर्यात कीमत			

चीन जन.गण.	107.09	94.13	-12.96
इंडोनेशिया	94.55	98.47	3.92

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि जांच अवधि में कच्ची सामग्री की लागत में 23.48% की वृद्धि हुई तथापि, चीन से निर्यातित कीमत में 12.10% की गिरावट आई जबकि इंडोनेशिया के मामले में इसमें केवल 4.14% की वृद्धि हुई है।

- नियमों के अंतर्गत कारणात्मक संबंध की अपेक्षा- ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पार्टियां नियमों की व्याख्या इस तरीके से कर रही हैं जिससे यह पता चले कि क्षति का एकमात्र कारण पाटित आयात होना चाहिए। लेकिन, जरूरत यह नहीं है। नियमों के अंतर्गत क्षति के प्रमुख कारणों में से एक कारण पाटित आयात होना चाहिए। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की कीमत आयात कीमत के अनुसार तय करता है और यह तथ्य कि घरेलू उद्योग कीमतों में अधोगामी संशोधन करने के लिए बाध्य हुआ है और वह भी कई बार सामान्य से अधिक सीमा तक, से इस बात की पुष्टि होती है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

10.2 जहां तक मानी गई निर्यात बिक्रियों और ऐसी बिक्रियों पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त पर्याप्त छूट से संबंधित मुद्दे का संबंध है, घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार उल्लेख किया है :

- घरेलू उद्योग एक सुस्थापित कीमत नीति का अनुसरण करता है। घरेलू उद्योग "कीमत सूची" के अनुसार उत्पाद की निकासी और बिक्री करता है। प्रत्येक बिक्री सौदे के लिए कीमत पर बातचीत नहीं की जाती है। घरेलू उद्योग भाव दरों, कीमत वार्ताओं, खरीद एवं ऑर्डर के निष्पादन का उल्लेख करते हुए व्यापार पूछताछों का उत्तर देने की प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है। घरेलू उद्योग "कीमत सूची" की घोषणा करता है और उसके बाद सामग्री की बिक्री घोषित कीमत सूची के आधार पर करता है। आपवादित परिस्थितियों को छोड़कर कंपनी द्वारा की गई सभी बिक्रियां कीमत सूची के अनुसार की गई हैं, जिसके साथ कीमत में संशोधन करने के बारे में विपणन कार्यकारी के प्रचालन स्तर पर कुछ या कुछ भी नहीं विवेकाधिकार हैं।
- घरेलू उद्योग की सूचीगत कीमत का उपयोग घरेलू उद्योग की कीमत के साथ आयातित उत्पाद की कीमत के साथ करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी किसी स्थिति में जिसमें कंपनी प्रत्येक बार कीमत पर बातचीत करने के बाद ग्राहक-दर-ग्राहक अलग-अलग कीमत पर अलग-अलग ग्राहकों को सामग्री की बिक्री करती है, वहां ऐसा करना संगत और उचित होगा कि अवधि के दौरान बची गई मात्रा की भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया जाए। तथापि, ऐसी किसी स्थिति में जहां कंपनी अपने उत्पाद की बिक्री पूर्व निर्धारित कीमत पर करती है, सार्वजनिक कीमत सूचियों की घोषणा करती है और जहां ऐसी कीमत सूचियों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करने के बाद की जाती है, वहां आयातित एवं घरेलू उत्पाद के बीच कीमत की तुलना ऐसी कीमत सूचियों के आधार पर की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह दोहराया है कि बिक्री कीमतें ग्राहकों के

साथ अलग-अलग नहीं रही हैं और इसलिए किसी खास अवधि में बेची गयी मात्रा की भारित औसत बिक्री कीमत का निर्धारण करने की कोई जरूरत नहीं है ।

- कीमत का निर्धारण वैज्ञानिक और पारदर्शी ढंग से किया जाता है । कीमत निर्धारण का आधार प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत होता है । प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए कंपनी अपनी मूलभूत कीमत निर्धारित करती है जिन्हें ऐसे अंतरों के आलोक में देखा जाना चाहिए जो अलग-अलग देशों में विद्यमान हैं (विनिमय दर, सीमाशुल्क आदि के अनुसार) ।
- कंपनी ने कुछेक श्रेणी की बिक्री का उल्लेख "माने गए निर्यातों" के रूप में किया है । विरोधी हितबद्ध पार्टियां इस बात से असहमत नहीं हैं कि माने गए निर्यात घरेलू बिक्री का भाग नहीं होना चाहिए । तथापि, महज इस वजह से कि कंपनी ने कुछेक बिक्रियों को ही माने गए निर्यातों के रूप में निर्दिष्ट किया है, ये बिक्रियां माने गए निर्यात नहीं बन जाती हैं ।
- माने गए निर्यातों को विदेश व्यापार नीति में परिभाषित किया गया है । मानी गई निर्यात बिक्रियों के अनिवार्य घटक निम्नानुसार हैं :

"मुख्य/उप संविदाकारों द्वारा माल की आपूर्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को एफटीपी के अंतर्गत "माने गए निर्यात" माना जाता है, बशर्त माल का विनिर्माण भारत में किया गया हो":

- (क) वार्षिक जरूरत/डीएफआईए हेतु अग्रिम प्राधिकार/अग्रिम प्राधिकार पर माल की आपूर्ति ।
- (ख) ईओयू या एसटीपी या ईएचटीपी या बीटीपी को माल की आपूर्ति
- (ग) ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत प्राधिकार पत्र धारण कर्त्ताओं को पूंजीगत माल की आपूर्ति ।
- (घ) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बहु पक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली (आईसीबी) के अंतर्गत इन एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति जब वित्तिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना निविदा के मूल्यांकन का प्रावधान हो ।
- (ङ) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आईसीबी के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार आईसीबी के अंतर्गत इन एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल तथा उपकरणों (आद्योपांत संविदाओं की एकल जिम्मेवारी) की आपूर्ति एवं

प्रतिष्ठापन, जिनके लिए बोलियाँ अस्त्रित की गई हों और उनका मूल्यांकन विदेश में विनिर्मित माल की डिलीवरीशुदा शुल्क संदत्त (डीडीपी) कीमत के आधार पर किया गया हो ।

(च) असंयोजित/वियोजित स्थिति में पूंजीगत माल सहित पूंजीगत माल एवं संयंत्र, मशीनरी, सहायक सामग्री, औजार, सांचों एवं ऐसी वस्तुओं, जिनका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के चरण तक प्रतिष्ठापन प्रयोजनों में किया जाता है तथा उर्वरक संयंत्रों को एफओआर मूल्य के 10% तक कलपुर्जों की आपूर्ति ।

(छ) किसी परियोजना या किसी परियोजना के लिए माल की आपूर्ति, जिसके संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति दी हो ।

(ज) उपर्युक्त (च) में असम्मिलित विद्युत परियोजनाओं और तेलशोधन शालाओं को माल की आपूर्ति ।

(झ) 100% ईओयू (घरेलू फ्रेट कंटेनर-विनिर्माता) द्वारा समुद्री भाड़ा कंटेनरों की आपूर्ति बशर्ते उक्त कंटेनर छः माह की अवधि के भीतर या सीमाशुल्क द्वारा अनुमत आगे की अवधि के भीतर भारत से निर्यात कर दिए गए हों ।

(ञ) यू एन एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को आपूर्ति; और

(ट) आईसीबी के विपरीत प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को माल की आपूर्ति ।

- चूंकि भारत सरकार मानी गई निर्यात बिक्री को निर्यात बिक्री मानती है तथा यह और कि क्षति का निर्धारण घरेलू बिक्री के लिए किया जाना चाहिए । इसलिए विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने सही ढंग से यह दावा किया है कि मानी गई निर्यात बिक्रियों को घरेलू बिक्री से अलग नहीं रखा जाना चाहिए ।

- घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिक्रियां मानी गई निर्यात बिक्री के रूप में पात्र नहीं हैं, यद्यपि उनके द्वारा बाजार में माने गए निर्यातों की शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है । वस्तुतः उपभोक्ता निर्यात लाभों का दावा उनके द्वारा किए गए निर्यातों के बारे में करते हैं और घरेलू उद्योग महज इस कारण से "माने गए निर्यात" शब्दावली का उपयोग करता है कि इस फाइबर का उपयोग ऐसे उत्पाद में किया गया है, जिसका निर्यात किया गया है । तथापि, समस्त निर्यात लाभ उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए हैं न कि घरेलू उद्योग द्वारा । यदि ये मानी गई निर्यात बिक्रियां होतीं, तो घरेलू उद्योग विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न लाभों का पात्र होता ।

- अतः यह अनुरोध किया जाता है कि वे विनिर्दिष्ट नहीं की गई निर्यात विनियमों नहीं हैं, जैसा कि विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने समझा है अर्थात्, वे केवल घरेलू विनियम हैं। अतः इन विनियमों को "घरेलू विनियम" शीर्ष के अंतर्गत उचित ढंग से सम्मिलित किया गया है।

झ. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है जिनमें घरेलू उद्योग का यह तर्क भी शामिल है कि उन्होंने तथ्यपरक "जाने गए निर्यातों" के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है। अतः ऐसी विनियमों को घरेलू विनियम माना जाना चाहिए। तथापि, इन दावों और प्रतिदावों की प्रति जांच आने की जाने वाली जांच और नौके पर सत्यापन की कार्यवाही के दौरान की जाएगी।

11.1 प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को दर्ज किया जाए और क्षति विश्लेषण निम्नानुसार किया है:

11.2 पाटनरोधी नियमों के अनुबंध II में यह अस्पष्ट है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और ; (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या क्षमता की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अल्पकालिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अल्पकालिक अल्पकालिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अल्पकालिक अवधि तक बढ़ गई होती।"

11.3 जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में निम्नी लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उद्योग में स्वाम्यधिक और संगठित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वार्षिक और संगठित वार्षिक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

11.4 प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए तथ्यों और दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है।

संचयी निर्धारण

12. चूंकि वर्तमान जांच में शामिल देश एक से अधिक हैं, इसलिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या संचयी निर्धारण हेतु शर्तों की प्रथम दृष्टया पूर्ति होती है या नहीं। प्राधिकारी ने यह पाया है कि :

- i. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित सीमाओं से अधिक है;
- ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है;
- iii. आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसा इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद निम्नलिखित आधार पर समान वस्तुएं हैं :- प्रत्येक संबद्ध देश से हुए आयात काफी अधिक रहे हैं; भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है; सामान्य पार्टियां आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का उपयोग कर रही हैं; भारतीय उत्पादक/ग्राहक घरेलू सामग्री तथा आयातित सामग्री का उपयोग कर रहे हैं; संबद्ध देशों के निर्यातकों और आवेदक ने एक ही श्रेणी के ग्राहकों को एक समान अवधि में एक समान उत्पाद की बिक्री की है आदि।

12.1 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण करना उचित होगा।

मांग एवं बाजार हिस्सा:-

13. देश में उत्पाद की मांग का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में किया गया है।

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि	अप्रैल-जून 08 - वार्षिक	जांच अवधि - वार्षिक
घरेलू उद्योग की बिक्री मी. ट. में	223,147	226,178	237,640	49,784	100,925	199,136	201,850
सूचीबद्ध	100	101	106	89	90	89	90
भारत में आयात मी. ट. में	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,560	12,658
सूचीबद्ध	100	3,415	3,450	3,812	6,382	3,812	6,382
मांग मी. ट. में	223,345	232,952	244,482	51,674	107,254	206,696	214,508
सूचीबद्ध	100	104	109	93	96	93	96
बाजार हिस्सा							
संबद्ध देश	0.06%	1.34%	2.77%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
अन्य देश	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
घरेलू उद्योग	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

13.1 यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2007-08 तक वृद्धि हो रही थी। तथापि, उसमें अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि के दौरान गिरावट (आनुपातिक आधार पर) आई है। यह भी नोट किया जाता है कि वृद्धि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट देखी गई है, तथापि मात्रा में पर्याप्त वृद्धि (आनुपातिक आधार पर हुई है)। कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि भारत में उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, आरोपित आयातों के कारण नहीं हुई है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में गिरावट के प्रभाव के परिणामस्वरूप आयातों में अनुपातिक आधार पर गिरावट आई होगी। तथापि, यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण प्रत्यक्षतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

13.2 आयातों में वृद्धि का यह प्रभाव आयातों के बाजार हिस्से में ही दृष्टिगोचर होता है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है।

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

14. संबद्ध वस्तु के आयातों और बाजार हिस्सों का नीचे निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल- जून 08	जांच अवधि	अप्रैल-जून 08 - वार्षिक	जांच अवधि - वार्षिक
संबद्ध देशों से आयात (मी.ट. में)	125	3,121	6,779	1,890	6,329	7,561	12,658
संबद्ध देशों से इतर देशों से आयात (मी.ट. में)	73	3,653	62	-	-	-	-
कुल आयात (मी.ट. में)	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,561	12,658
भारतीय उत्पादन की तुलना में पाटित आयात %	0.09%	2.74%	2.46%	3.27%	5.54%	3.27%	5.54%
भारत में मांग की तुलना में पाटित आयात %	0.06%	1.34%	2.77%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
मांग में बाजार हिस्सा							
संबद्ध देश	0.06%	1.34%	2.77%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
अन्य देश	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
घरेलू उद्योग	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

14.1 यह देखा गया है कि:-

- आयातों में समग्र रूप में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
- आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

- जहां संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग पर आयातों का प्रभाव प्रतिकूल रहा है।

आयातों का कीमत प्रभाव

15. निम्नलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि कीमत में मामूली ऋणात्मक कटौती हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि वह विद्याराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य के अनुसार संबद्ध वस्तु की कीमत तय करता है और यह तुलना निवल बिक्री कीमत में उस कारोबार छूट को शामिल करने के बाद की जानी चाहिए जो वह अपने ग्राहकों को प्रदान करता है, जो कि प्राप्त कारोबार के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिक होता है; और यदि इस कारोबारी छूट को औसत बिक्री कीमत में शामिल किया जाएगा तो कीमत कटौती अत्यधिक सकारात्मक होगी।

	चीन जन.गण.	इंडोनेशिया
सीआईएफ निर्यात कीमत	94.13	95.39
पहुंच कीमत	98.89	100.21
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	***	***
कीमत कटौती	***	***
कीमत कटौती % रेंज	-1% to 1%	-2% to 2%

15.1 घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव प्रतिकूल रहा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-

प्राधिकारी ने उत्पादन लागत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ-साथ आयातों की पहुंच कीमत की आगे तुलना की है जो निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है :

रु./किग्रा	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून, 08	जांच अवधि (जुलाई-दिसंबर, 2008)
उत्पादन लागत	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	102	108	137	146
बिक्री कीमत	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	116	140	150	134
चीन जन.गण. से पहुंच कीमत	137.65	86.40	112.50	110.64	98.89
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100.00	63	82	80	73
इंडोनेशिया से पहुंच कीमत	77.08	87.39	99.33	107.62	100.21
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	113	129	140	131

15.2 यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 134 हो गई है। तथापि, इसकी उत्पादन लागत आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच

अवधि में 146 हो गई है। स्पष्टतः घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में बढ़ोतरी नहीं कर सका; जिससे यह पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक ह्रास हो रहा था।

15.3 प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है और यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम रहा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

रु./किग्रा. में

	एनआरसी	पहुंच कीमत	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री % रेंज
चीन जन.गण.	***	98.89	***	5 से 15
इंडोनेशिया	***	100.21	***	5 से 15

15.4 स्पष्टतः घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु की बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

16. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन उत्पादों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में गिरावट; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक; नकद प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों की तथ्यपरक और निष्पक्ष जांच शामिल होनी चाहिए। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

बिक्री मात्रा

17. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि	अप्रैल-जून 08- वार्षिक	जांच अवधि - वार्षिक
बिक्री मात्रा	223,147	226,178	237,640	49,784	100,925	199,136	201,850
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	101	106	89	90	89	90

17.1 यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2007-08 तक बिक्री हुई थी और उसके बाद अप्रैल-जून, 08 की अवधि तथा जांच अवधि में गिरावट आई थी। यद्यपि, मांग में

गिरावट आई है तथापि, मांग में गिरावट आने के कारण आयातों में आनुपातिक रूप से गिरावट नहीं आई है, अपितु उनमें वास्तविक वृद्धि हुई है।

क्षमता और क्षमता उपयोग

18. क्षमता एवं क्षमता उपयोग से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि	अप्रैल-जून 08- वार्षिक	जांच अवधि वार्षिक
क्षमता	257,325	266,450	266,450	82,425	166,935	329,700	333,870
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	104	104	128	130	128	130
उत्पादन	228,981	246,832	277,818	57,829	114,314	231,317	228,628
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	108	121	101	100	101	100
क्षमता उपयोग	88.99%	92.64%	104.27%	70.16%	68.48%	70.16%	68.48%
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	104	117	79	77	79	77

18.1 यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2007-08 तक सुधार हो रहा था जिसमें अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि में गिरावट आई। कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने मार्च, 2008 में अपनी क्षमता में वृद्धि की थी और किसी नई क्षमता द्वारा पुरानी क्षमता के बराबर कार्य निष्पादन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने क्षमता के उसी स्तर पर जो विस्तार से पूर्व विद्यमान था, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच की है और यह नोट किया है कि क्षमता के एक समान स्तर होने के बाद भी क्षमता उपयोग वर्ष 2007-08 में 104.27% से घटकर जांच अवधि में 85.8% हो गया।

लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ

19. लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि	अप्रैल-जून 08- वार्षिक	जांच अवधि वार्षिक
पीबीटी-लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	169	271	127	73	127	73
पीबीटी रु./किग्रा.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	166	255	142	81	142	81
पीबीआईटी रु. लाख में	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	163	258	130	97	130	97
नकद लाभ लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	163	255	131	84	131	84
आरओआई एनएफए आधार पर	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	149	171	82	57	82	57
आरओआई जीएफए आधार पर	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	149	186	94	63	94	63

19.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभप्रदता में वर्ष 2007-08 तक सुधार हो रहा था जिसमें तत्पश्चात पर्याप्त गिरावट आई थी। निवेश पर आय एवं नकद लाभ में भी लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति देखी गई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान निवेश पर औसत आय सकारात्मक थी, तथापि क्षति अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट आई। प्राधिकारी ने जांच अवधि के भीतर तिमाही आधार पर घरेलू उद्योग के लाभ एवं आरओआई स्थिति की आगे जांच की थी। आगे यह नोट किया गया है कि जांच अवधि की दूसरी तिमाही में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है

	जुलाई-सितं. 08	अक्टू.-दिसं. 08	जांच अवधि (जुलाई-दिसंबर, 2008)
आरओआई (लगाई गई पूंजी को एनएफए आधार पर मानते हुए)	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	76	35	57
आरओआई (लगाई गई पूंजी को जीएफए आधार पर मानते हुए)	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	85	39	63

मालसूची:

20. घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर निम्नानुसार रहा है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि (जुलाई-दिसंबर 2008)
मालसूची	13654	5236	8233	13587	13539
बिक्री दिवसों की संख्या के आधार पर मालसूची	20	7	11	21	20

20.1 यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2006-07 में गिरावट आई जिसमें वर्ष 2007-08 में पुनः वृद्धि हुई। अप्रैल-जून, 08 की अवधि एवं जांच अवधि के दौरान वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में मालसूची में पुनः वृद्धि हुई।

रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

21. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि (जुलाई-दिसंबर 2008)
रोजगार	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	97	96	96	95
रोजगार प्रति 1000 एम टी	***	***	***	***	***

क्षमता					
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	94	93	75	73
उत्पादकता प्रति दिन (मी.ट.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	108	121	101	100
उत्पादकता प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष (मी.ट.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	111	126	105	105

21.1 यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में गिरावट आई थी। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह गिरावट न केवल जांच अवधि में देखी गई है अपितु यह जांच अवधि से पूर्व भी विद्यमान थी। घरेलू उद्योग की मजदूरी में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित होती है। जहां तक प्रति कर्मचारी उत्पादकता का संबंध है, इसमें वर्ष 2007-08 तक वृद्धि हुई और अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि के दौरान गिरावट आई।

पाटन मार्जिन:

22. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक और निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

वृद्धि

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री (आधार वर्ष से 10% और वर्ष 2007-08 से 15% की गिरावट) उत्पादन (वर्ष 2007-08 से 18% और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 23% और वर्ष 2007-08 से 34% की गिरावट) जैसे मात्रात्मक मापदंडों के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक रही है। मूल्य संबंधी मापदंडों में वृद्धि भी ऋणात्मक देखी गई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ (आधार वर्ष से 27% और वर्ष 2007-08 से 73% की गिरावट) तथा निवेश पर आय (आधार वर्ष से 43% और वर्ष 2007-08 से 67% की गिरावट) में भी भारी कमी आई है।

वास्तविक क्षति का खतरा

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों की वृद्धि दर अत्यधिक है जिससे अत्यधिक संवर्धित आयात की संभावना का पता चलता है। कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है तथा भारी कीमत ह्रास हुआ है जिससे आयातों में संभावित वृद्धि का पता चलता है और जिसका घरेलू कीमतों पर पर्याप्त ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। तथापि, वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में किए गए दावों की जांच विस्तृत रूप से जांच की कार्यवाई के दौरान की जाएगी।

वास्तविक क्षति के बारे में निष्कर्ष

25. यह देखा गया है कि लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्से के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के भीतर घरेलू उद्योग के निष्पादन की तिमाही आधार पर जांच भी की है। यह

गिरावट जांच अवधि की दूसरी तिमाही में तिमाही निष्पादन के संबंध में काफी अधिक रही है। उपर्युक्त मापदंडों की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को प्रत्यक्ष वास्तविक क्षति हुई है।

अ. कारणात्मक संबंध

26. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या बाह्यदेशी निष्पादनी में सूचीबद्ध अन्य मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। इस संबंध में निम्नानुसार पाया गया है :-

तीसरे देशों से आयात

26.1. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से संबद्ध वस्तु के आयात के सौदेवार आंकड़े एकत्र किए हैं। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है।

मांग में कमी:-

26.2 प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में वर्ष 2007-08 तक पर्याप्त सुधार प्रदर्शित हुआ है और तत्पश्चात जांच अवधि में गिरावट देखी गई है। तथापि, मांग की तुलना में आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो सामान्यतः मांग में गिरावट के कारण नहीं होनी चाहिए थी। प्राधिकारी को खपत की पद्धति में कोई खास परिवर्तन नहीं मिला है। रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। आवेदक ने दावा किया है कि प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है और किसी भी हितबद्ध पार्टी ने आवेदक के दावे का खंडन नहीं किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में मामूली गिरावट आई है, तथापि घरेलू एवं निर्यात बाजार में कीमत एवं लाभप्रदता का विश्लेषण अलग-अलग आधार पर किया गया है। अतः क्षति संबंधी विश्लेषण निर्यात निष्पादन के कारण अप्रतिनिधिक नहीं है।

26.3. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंडों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है :

- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, तथापि संबद्ध देशों से हुए आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- कम कीमत पर बिक्री हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है।
- पाटित आयातों के कारण हुए अत्यधिक कीमत ह्रास की वजह से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे लाभ एवं नकद प्रवाह में भारी गिरावट आई है।

26.4 अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

ट. निष्कर्ष

27. हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

(क) संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;

(ख) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; अतः उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

28.1 प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी खासकर तब जबकि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाएगा। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकेंगे।

ड. सिफारिशें

29 प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पार्टियों को दी गई थी और निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे प्रारंभिक जांच शुरू करने के बाद तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की अनंतिम रूप से पुष्टि करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूरी होने तक पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे उल्लिखित प्रपत्र में और तरीके से निम्नानुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

29.1 प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को काल में रखने हुए प्राधिकारी फाटन मार्जिन और "क्षति" मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर अन्तिम फाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" समाप्त की जा सके। तदनुसार संबद्ध देशों के मूल की वा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार जानी की जाने वाली अविशुद्धता की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर अन्तिम फाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है।

क्र.सं.	सीमा / एन सीटी	वस्तु विवरण	अन्तः का देश	निर्गत का देश	उत्पत्ति	निर्गत	शुल्क की राशि	इकाई	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	इ. सी. टी. सी. टी. वैश्विक निर्यात	इ. सी. टी. सी. टी. वैश्विक निर्यात		किग्रा.	अन. सी.
2	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	सी. टी. इ. सी. सी. टी. वैश्विक निर्यात	सी. टी. इ. सी. सी. टी. वैश्विक निर्यात		किग्रा.	अन. सी.
3	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	क्र.सं. 1 और 2 पर दिए गए वर्णों के द्वारा कोई भी देश			किग्रा.	अन. सी.
4	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया से हजार कोई देश	जहाँ	जहाँ		किग्रा.	अन. सी.
5	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	फाटनरोधी शुल्क के अन्तिम देश से हजार कोई देश	इंडोनेशिया	जहाँ	जहाँ		किग्रा.	अन. सी.
6	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	चीन कान. कान.	चीन कान. कान.	जहाँ	जहाँ		किग्रा.	अन. सी.
7	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	चीन कान. कान.	चीन कान. कान. से हजार कोई देश	जहाँ	जहाँ		किग्रा.	अन. सी.
8	5504.10.00	"जोड़ के काष्ठों की छोड़कर निर्यात योग्य कच्चा (विरचय)"	फाटनरोधी शुल्क के अन्तिम देश से हजार कोई देश	चीन कान. कान.	जहाँ	जहाँ		किग्रा.	अन. सी.

ड. आगे की प्रक्रिया

30. प्रारंभिक जांच परिणामों को अविशुद्धित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

- (क) प्राधिकारी समस्त हितबद्ध पार्टियों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करेंगे जिन पर अन्तिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा;
- (ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, आवेदक और संबंधित समझी जाने वाली अन्य हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है, जो इन जांच परिणामों के प्रेषण की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इस जांच परिणाम के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है।

- (ग) प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के विचारों की मौखिक सुनवाई करने के लिए एक सुनवाई आयोजित करेंगे।
- (घ) प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे और सत्यापन किया जाएगा;
- (ङ) प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमों के अनुसार अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2009

Subject : Anti-dumping Investigation concerning import of "Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre" originating in or exported from China PR and Indonesia—Preliminary Findings.

No. 14/6/2009-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed.
 - i. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the above Rules, received a written application from Association of Man Made Fibre Industry of India (AMFII) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' (hereinafter also referred to as the subject goods); originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter referred to as subject countries).
 - ii. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented.
 - iii. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
 - iv. The Authority issued a public notice dated 19th March 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.

- v. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicant) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
- vi. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
- vii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods made in India during the past three years and the period of investigation. The information received from DGCI&S was analyzed and the same was compared with the information received from the respondents from Indonesia. It was found that the respondents have reported higher volumes of exports of subject goods to India during the POI. Thus, the imports data has been compiled and collated on the basis of DGCI&S data and the information received from the respondents from Indonesia.
- viii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- ix. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
- P.T.South Pacific Viscose
 - Hebei Jigao Chemical Fiber Co.,Ltd
 - Kunshan Hengsheng Chemical Fiber Co
 - Zibo Hualong Chemical Fiber Co., Ltd.
 - Hubei Chemical Fiber Group Ltd.,
 - Gaomi Silver Hawk Chemical Fibre Co. Ltd
 - Sateri(Jiangxi)Chemical Fiber Co., Ltd
 - Fulida Group Holding Co.,Ltd
 - Manasi Aoyang Technical Co.,Ltd
 - Yibin Grace Group Co.,Ltd
 - PT. Indo Bharat Rayon
- x. In response to the initiation notification, the following exporters / producers from Indonesia have responded:
- M/s PT Indo Bharat Rayon
 - M/s PT South Pacific Viscose

- xi. Neither the producers and exporter from China PR have responded, nor have they filed any relevant information and made any submission.
- xii. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

<ul style="list-style-type: none"> • Pallava Textiles • Cheran Spintex (I) Ltd., • Pallipalayam Spinners, • Shri Cheran Syn. India Ltd. • Keshar Multiyarn Mill Ltd. • Soundararaja Mills Ltd., • Ginni Filaments Ltd. • PKPN Spinning Mills (P) Ltd. • Adani Enterprises Ltd. • Rajapalayam Mills Ltd. • Sutlet Inds. Ltd. • Pallava Textiles • Zenith Spinners, • Cheran Spintex (I) Ltd., • Bee Vee Textiles, • Birla Textiles Mills, • AGT Mills P. Ltd. • Mothi Spinner Ltd, • Orient Syntex, • SMP Textile Mills (P) Ltd. • Keshar Multiyarn Mill Ltd. • Keshar Multiyarn Mill Ltd. • Samangal Synthetics, • Shree Rajasthan Syntex Ltd, • Maharaja Sathayam Ind. Pvt. • SMP Textile Mills (P) Ltd. • Nahar Spinning • Chola Spinning Mills P Ltd, • PKPN Spinning Mills (P) Ltd • Sri Karthikaya Spg & Wvg Mills, • KRV Spinning Mills P. Ltd. • Velatal Spinning Mills P Ltd, • Sree Dinakar Fabrics • Arcot Textile Mill Ltd • Valli Spg Mills • Banswara Syntex Ltd, 	<ul style="list-style-type: none"> • RSWM Ltd. • Reliance Chemotex Ind Ltd, • Shree Rajasthan Syntex • Pallipalayam Spinners, • Rajaguru Spinning Mills, • Deepak Spinners Ltd, • Ankur Ugyog Chola Spg Mills • PKPN Spinning Mills (P) Ltd – • Gimatex Industries Pvt. Ltd., • Sri Bhagirath Textiles Ltd, • Soundararaja Mills Ltd., • Suryalata Spinning Mills • Gillanders Arbuthnot & Co. • Victory Spg. Mills, • Arunkumar Spinning Mills P., • RSWM Ltd • Cheran Spinner Ltd • Shree Bharani Spinning • Sutlet Inds. Ltd. • Rajaguru Spinning Mills, • Pallava Textiles • Sidharth Exports Pvt. Ltd., • Choleeswarar Spinning Mills, • Soundararaja Mills Ltd., \ • Sree Karpagambal Mills • Sri Hanprasath Textiles • Vardhman Textile Ltd. • Sri Nallathal Spinning Mills • Mothi Spinner Ltd, • Supertex Mills India Pvt. Ltd., • GVS Spinners, • Nru Spinning Mills • Saraf Yarn Pvt. Ltd • Sangam Spinners Ltd. • Chenab Textile Mills , • Spentex Industries Ltd • Suryalata Spinning Mills
--	---

- xiii. In response thereof, following have responded:
- Indian Spinners Association – Mumbai
 - Shree Rajasthan Syntex Ltd
 - Suryalata Spinning Mills Ltd
 - Spentex Industries Ltd
 - Pee Vee Textiles Ltd
 - Shree Cheran Synthetics India Ltd
 - Pallava Textiles Ltd
 - RSWM Ltd
 - Pallipalayam Spinners Pvt Limited
- xiv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xv. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvi. Investigation was carried out for period starting from 1st July 2008 to 31st Dec 2008 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from 2005-06, 2006-07, 2007-08, April 08-June 08 and POI.
- xvii. *** in this notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND DOMESTIC LIKE ARTICLE

3. The product under consideration is "**Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre**". Viscose Staple Fibre is described as "**Viscose rayon staple fibre not carded/combed**" under the Customs Tariff and is also known as "**Rayon Fibre**" in some markets. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504.10.00. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3.1 Viscose Staple Fibre was the first man-made fibre, and unlike other man-made fibres, is not a synthetic fibre. It is made through wet spinning technology and is a regenerated cellulose fibre made from wood pulp, which is essentially cellulose extracted from a sustainable natural resource i.e. wood, by subjecting it to various chemical and mechanical processes. On account of its cellulosic base, viscose staple fibre properties are similar to those of natural cellulosic fibres than those of thermoplastic, petroleum based synthetic fibres such as nylon or polyester. Further, it has a distinct advantage of engineered specification and uniformity.

3.2 Viscose Staple Fibre has silk-like aesthetic with superb drape, soft feel and retains rich brilliant colours. Fabrics made from it are moisture absorbent (even more than cotton), breathable, comfortable to wear, and easily dye able in vivid colours. They do not build up static electricity, and are pill-resistant.

3.3 Main strength of VSF is its versatility and ability to blend easily with nearly all other textile fibres to impart lusture, softness, absorbency and resulting comfort to the fabric made from such blends. Bamboo fibre, one of the types of Viscose Staple Fibre is excluded from the scope of this investigation. In the initiation notification, Designated Authority has specifically requested the interested parties to make their submissions with regard to exclusion of Bamboo Fibre. None of the interested parties had made any submissions in this regard.

3.4 With regard to like article, Rule 2(d) of the AD rules provides as under:

"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation

3.5 The applicant has claimed that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries. Subject goods produced by domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. None of the opposing interested parties have raised any objection in this regard.

3.6 The available information at this stage does not show that there is any material difference in the domestic like article and imported subject goods. Thus, subject goods produced by the domestic industry is being treated as like article to the subject goods imported from subject countries in accordance with the AD rules for the purpose of the present investigation.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

4. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"Domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry:

4.1 The application has been filed by Association of Man Made Fibre Industry of India on behalf of the domestic industry. M/s Grasim Industries Ltd. is the sole

producer of the Like Article in India and has provided injury and costing information. The applicant has claimed that there is no other producer of the Like Article in India. As per the evidence available on record, production of M/s Grasim Industries Ltd. accounts for a major proportion of the domestic production. The production of M/s Grasim Industries Ltd. is more than 50% of Indian production.

4.2 M/s Grasim Industries Ltd. has affiliated companies in Indonesia and China PR producing & selling the product, namely Birla Jingwai Fibres Company Limited, China and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia. The Chinese affiliated company has not exported the product to India, whereas the Indonesian Company has exported small quantity to India, which is less than 3% of imports and negligible with reference to Indian production. Since the volume of these imports are quite small, the Authority considers it appropriate to hold that the Applicant is not required to be excluded from the scope of the domestic industry under Rule 2(b). None of the opposing interested parties have raised any issue in this regard. M/s PT Indo Bharat Rayon – Indonesia have also filed their detailed response to the questionnaire sent.

4.3 Thus, the Authority has determined that the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Further, M/s Grasim Industries Ltd. is being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. OTHER ISSUES

5. Following submissions have been made by Indian Spinners Association:

- They have objected to the data collected by domestic industry from secondary source. They consider that it was bounden responsibility of the Applicant to give official data. Since data given by the Applicant is not official, conclusion reached by the applicant is wrong.
- Due to recession conditions, consumption of fabric has been greatly affected all over the world and it has impacted prices of not only fabrics but also yarn and fibre including viscose staple fibre
- The Applicant has always operated on full capacity except when there is water shortage at its NAGDA plant. But in 2008-09 because of recession, it has closed down its Kharach Plant and capacity utilization is also affected.
- Average CIF price of imports during the POI is higher than average CIF price of 2007-08.
- Basic problem with the domestic industry is continuous increase of capacity without taking into account changing of trends.
- The Applicant has vast resources and worldwide contacts, must be on front foot to help spinning industry.
- Applicant is the sole producer of product concerned in India. Imposition of anti dumping duty will create monopolistic situation in favour of Grasim and their group companies, which has large VSF capacities in other countries including Thailand.

5.1 Submissions made by P T South Pacific Viscose

- Six month period of investigation is too short for assessment and analysis of dumping and injury to the domestic industry. Trade notice issued by the Designated Authority earlier also clearly mandates that the period of investigation should normally be twelve months.
- Product concern has dedicated customs code; therefore, consideration of secondary source as basis of imports is not justified.
- DGCIS data shows much higher volumes compared to secondary source and at higher prices.
- There have been imports from other countries as per DGCIS, however, Applicant claims that no imports have been made from other than subject countries.

5.2 Submissions by the Domestic Industry

- Period of investigation – The petition contains specific reasons for consideration of six months as the investigation period. It is not even the argument of interested parties that six months investigation period is impermissible. Even the trade notice uses the word “normally” and not “always”. Relevant extracts of decision of CESTAT in the matter of HAS have been enclosed, wherein the Tribunal has clearly held that there is no bar in consideration of six months as investigation period. As regards reasons for choosing six months period, the petition contains the same. The argument to such an extent is factually incorrect.
- The petitioner clearly mentioned that the information has been procured from TIPS. Such being the case, the argument that the source has not been mentioned is without basis. As regards use of DGCIS data, the same could not have been adopted for the reason that the product under consideration does not have dedicated customs classification. The interested parties appear to have some misunderstanding that the product under consideration has dedicated customs classification. Further, transaction-by-transaction data can be available only after an application is filed before the Designated Authority. As regards comparison of DGCIS data with petition data, since the product scope itself does not include all types of VSF, any comparison with the DGCIS data is, at the least, misleading.
- Kharach plant of the company earlier had two production lines. Two more lines were added, which commenced production in March-April 2008 period. These capacity additions were based on the market feedback given by the consumers. In fact, the company had planned capacity expansion only upon feedback received from the customers that the product had good demand. However, because of dumping and adverse market situation, these two lines could not be fully utilized in the investigation period.

Examination by the Authority

5.3 The Authority has noted the submissions made by the interested parties regarding period of investigation and is of the view that the period of investigation chosen in the instant matter has been appropriately chosen considering the facts of the case, which also covers the most recent available data on the subject. Besides, the decision to take six-months period as POI has also been upheld by the Hon'ble tribunal in the matter of Virchow laboratories ltd. v/s Ministry of Finance.

5.3.1 The Authority notes that product under consideration in the present investigation is Viscose staple fibre – except bamboo fibre. Customs classification for the product under consideration does not exclude bamboo fibre. Therefore, summary information published by the Applicant cannot be relied upon as it may include imports of product other than product under consideration. The domestic industry has furnished information as provided by TIPS, which was accepted at the time of initiating the investigation

5.3.2 The domestic industry has alleged that significant import volumes have been reported under customs subheading no. 5504 9090. The Authority requested the O/o DGC&S for import information for custom classification nos. 55041000 and 55049090, which has been received and analysed. Accordingly imports volumes of the subject goods have been determined. A comparison of imports claimed by the Applicant as per TIPS data and as per DGC&S data shows the following:

	TIPS data		DGC&S data	
	Qty Kg	Rs./Kg	Qty Kg	Rs./Kg
China PR	907252	96.03	1023971	94.13
Indonesia	4533741	98.44	4689364	98.47

5.3.4 From the material available on record, it is seen that there are no imports of the subject goods from any other country except from the subject countries. The volume and price as per DGC&S and TIPS are broadly comparable.

E. DUMPING MARGIN

6. The Authority sent the questionnaire to known exporters and producers of product under consideration in Indonesia and China PR. Only the following two producers from Indonesia have responded thereto and filed their responses.

- M/s PT Indo Bharat Rayon
- M/s PT South Pacific Viscose

DETERMINATION OF NORMAL VALUE FOR COOPERATING EXPORTERS AND PRODUCERS FROM INDONESIA

M/s P T SOUTH PACIFIC VISCOSE

6.1 M/s. P T South Pacific Viscose from Indonesia has responded and provided information. Certain deficiencies were observed in the response filed and clarifications sought. The company has furnished information relating to domestic sales in Appendix 1 and exports to India in Appendix 2. The Company has furnished information relating to cost of production in Appendix 5, 6 to 8. A perusal of the data shows that the company's weighted average domestic sales price is lower than the weighted average domestic cost of production. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction-wise domestic sales and it has been found that 17.13% of the domestic sales are profitable. Thus, the Normal value has been determined on the basis of profitable domestic sales. The adjustments claimed on account of commission, bank charges and credit cost are being provisionally allowed, subject to further investigation and spot verification. Thus, the Normal value is worked out as USD 2.226 per KG.

M/s PT INDO BHARAT RAYON

6.2 M/s. P T Indo Bharat Rayon from Indonesia has responded and provided information in the form and manner prescribed. The respondent has furnished information relating to domestic sales in Appendix 1. The respondent has furnished information relating to cost of production in Appendix 5 to 9. The Authority notes that the respondent has made profit on overall basis on its domestic sales. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction-wise domestic sales and it has been found that 78.82% of the domestic sales are profitable. Thus, the Normal value has been determined on the basis of profitable domestic sales. The adjustments claimed on account of freight, insurance and credit cost are being provisionally allowed, subject to further investigation and spot verification. Thus, the Normal value is worked out as USD 2.132 per KG.

Methodology: One normal value – country as a whole

6.3 Normal value has been determined for Indonesia as a whole. For this purpose, the Normal values determined for cooperating exporters as discussed above and weight of their profitable sales in domestic market have been considered as shown in the table below:-

Name	M/s P T SOUTH PACIFIC VISCOSE	M/s PT INDO BHARAT RAYON	Weighted Average
Normal Value	2.226	2.132	2.144
Profitable Domestic Sales in KG	5,667,754	40,031,669	45,699,423

F EXPORT PRICE**Ms P T SOUTH PACIFIC VISCOSE**

7.1 The information/data submitted by the respondent is being relied upon provisionally for the determination of the export price subject to further investigation and spot verification. The respondent has claimed adjustments on account of ocean transportation, credit costs and bank charges; the same are provisionally accepted subject to further investigation and spot verification. Thus, the Authority has determined the export price for the exporter as USD 2.017 per KG for the purposes of the preliminary findings.

Ms PT INDO BHARAT RAYON

7.2 The information/data submitted by the respondent is being relied upon provisionally for the determination of the export price subject to further investigation and spot verification. The respondent has claimed adjustments on account of international freight, inland transportation, international insurance, internal insurance and other expenses; the same are provisionally accepted subject to further investigation and spot verification. Thus, the Authority has determined the export price for the exporter as USD 1.927 per KG for the purposes of the preliminary findings.

DETERMINATION OF NORMAL VALUE & EXPORT PRICE FOR NON-COOPERATING EXPORTERS AND PRODUCERS FROM INDONESIA

7.3 No other exporter and producer from Indonesia has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Normal value & Export price based on facts available on record.

DETERMINATION OF NORMAL VALUE FOR CHINA PR.

7.4 The Authority sent questionnaire to the known exporters from China PR, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, no response has been received to the questionnaires from any of the Chinese producer/exporter.

7.5 Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of

development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

7.6 The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules.

7.7 As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:-

- a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

7.8 The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority, none of the Chinese producers/exporters have submitted any response including the market economy questionnaire response and sought to rebut the non-market economy presumption. In the initiation notification itself, the Authority had indicated that the Applicant has suggested Indonesia as appropriate surrogate country. Interested parties were requested to make submissions in this regard. However, none of the exporter/producer from China PR has responded and made any submissions in this regard. The Authority has therefore considered Indonesia as

appropriate surrogate country for China PR and determined Normal value in Indonesia as USD 2.144 per KG. The Authority also constructed the Normal value for China PR but found that the Normal value based on Indonesia as appropriate surrogate country is lesser than the constructed Normal value and therefore the Authority has determined the Normal value for China PR based on Indonesia as the appropriate surrogate country for the purposes of the preliminary findings.

DETERMINATION OF EXPORT PRICE FOR CHINA PR.

8. As none of the producer/exporter from China PR has responded, the Authority has therefore, determined the Export price as per facts available on record. The Authority notes that Applicant has furnished transaction-wise information as per secondary sources. Subsequently, the Authority procured the imports data from DGCI&S. The Authority has therefore determined export price for all exporters/producers from China PR based on facts available on record. The Export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses and bank commission, as per information available on record. The Export price so determined works out to USD 1.878 per KG.

G. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

9. Considering the Normal value and the Export price as determined above, the dumping margin works out as follows:

	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin %
Indonesia				
M/s PT South Pacific Viscose	2.144	2.017	0.127	6.30%
M/s PT Indo Bharat Rayon	2.144	1.927	0.217	11.26%
All Other except the two Companies mentioned above	2.144	1.384	0.760	54.91%
China PR				
All exporters and producers	2.144	1.878	0.266	14.16%

9.1 The Authority notes that dumping margins from China PR and Indonesia are more than the de-minimis limits prescribed.

H. INJURY

Submissions by M/s PT South Pacific Viscose – Indonesia

10. It has been contended by the M/s PT South Pacific Viscose that:

- There is decline in demand, which have affected the domestic industry; therefore, alleged dumped imports are not responsible for injury to the domestic industry.
- Price revision offered by the domestic industry has nothing to do with the alleged dumped imports from subject countries.
- Lower profitability of the domestic industry is mainly on account of increased input cost, lower volumes and weak margins. Interest and depreciation cost appears to be very high, which may be reason of lower profitability of domestic industry.
- Domestic industry, despite the restrained outlook, expended its capacity in March 2008. It is not possible for any industrial unit to achieve same level of capacity at very beginning of operations.
- Sales volume declined but not because of alleged dumping.
- Domestic industry is continuing with expansion project despite the alleged dumping of subject goods and the global recession. Therefore, there is no injury to the domestic industry so far investment and expansion program are concerned.
- No evidence is given with regard to threat of any material injury.
- Domestic industry follows a pricing policy through it gives a substantial rebate. Designated Authority should analyze the pricing policy before accepting any claim of injury to the domestic industry.
- Major imports from Indonesia are against advance license.
- There is no causal link between the alleged dumping and injury to the domestic industry.
- The petitioner is selling significant volumes in the domestic market on deemed exports basis on which significant discounts are being offered by the petitioners. These sales are not domestic sales and should be excluded from the domestic sales for the purpose of the present investigation.

- The company is offering significant discounts in sales in domestic market, which is evident from the price list of petitioners itself. Injury to the domestic industry, if any is on account of its own pricing policy and not due to alleged dumping.

Submissions by the domestic industry

10.1 It has been contended by the domestic industry that:

- The performance of the domestic industry in respect of most of the parameters was improving till 2007-08. However, the performance deteriorated in terms of domestic sales, production, capacity utilization, productivity, inventories, market share, profits, return on investments, cash flow, etc. Performance of the domestic industry in respect of some of the more critical parameters started dramatically deteriorating in POI, which position worsened at the end of POI.
- The current price offers coupled with huge unutilized capacities with the Foreign Producers is threatening further deterioration in performance. The domestic industry has suffered injury as a result of dumping.
- The rate of increase of dumped imports is significant, indicating the likelihood of substantially increased importation;
- Significant price difference and consequent potential increase in imports is having significant depressing effect on domestic prices;
- The Foreign Producers and Indian Producers are resorting to production cuts. Subject exporters are holding significant freely disposable capacity indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
- The present offers being made by the Foreign Producers mean unprecedented price reductions. These price reductions are an outcome of huge surpluses with them. Should the domestic industry match the prices being offered by the Chinese producers, it would lead to huge financial losses. Should the domestic industry prefer not to reduce the prices, it would mean a still higher disaster in terms of reduction of sales, followed by reduction of production -- increase in cost of production - increase in Financial losses.
- Price revisions and reductions –the pricing policy clearly establishes that the company fixes its price primarily based on landed price of imports. As regards letter to shareholders in the annual report for the year 2007-08, the investigation period in the present case is July-Dec.08 (and not 2007-08). Reference to annual report is highly misplaced.
- Profitability – The interested parties concede that lowering of profitability is due to "increasing input cost", "lower volume" and "weak margin" – all of which

are linked to dumped imports. While inability to pass on increasing input costs is reflective of adverse price effect, weak margin is another factor reflective of price suppression caused by imports. As regards lower volumes, while the decline in demand has already impacted in terms of lowering of sales, the increased imports have further compounded the injury of the domestic industry. As regards higher interest and appreciation compounded, reference is invited to the decision of the CESTAT in the matter of NBR, wherein it has been held that the domestic industry must be seen as it exists and not under ideal conditions. Indeed annual report for 2007-08 clearly refers to increasing input costs and softening VSF prices. Given the pricing policy of the company, it is evident that softening VSF price is because of softening of import prices. The Q2 and Q3 FI 2008-09 presentations clearly highlight inability of the company to pass on the cost increases to the customers.

- Capacity, production and capacity utilization – Capacity expansions are undertaken based on medium and long-term business outlook and not based on short-term adverse business situations created due to dumping. Before undertaking capacity expansion, the company took feedback from the consumers. The capacity additions were done by the company considering market analysis/ feedback from customers. In fact, the company has not even fully expanded to the extent the consumers had suggested the market demand. Such being the case, it is incorrect on the part of these consumers now to allege that the company has expanded beyond capacity. It would also be relevant to point out that the expanded capacity commenced commercial production from March-Apr., 2008. The profitability of the company was much better in the period April-June, 2008. The alleged impact of interest & depreciation must have been felt in this period as well.
- Threat of injury – The current capacity with the foreign producers and their domestic demand can be seen in the responses on record. It would be seen that the foreign producers are faced with significant surplus capacities. The Applicant has earlier provided copy of offer in the petition. In any case, the orders placed at these offers have landed in the Country. The Designated Authority may therefore kindly examine the questionnaire responses of the responding exporters.
- Imports under Advance license - By their own admission, not all imports made by the exporter were under advance license. Based on this, there is no justification for exclusion of these imports from the calculation of demand. Furthermore, the domestic industry competes with these imports by offering rebates to the consumers. Thus, the consumer has an option of buying imported material under advance license or buying from the domestic industry and selling the same in export market. In order to compete with these advance license imports, the domestic industry is offering a rebate. Therefore – (a) imports under advance license cannot be excluded for the purpose of assessment of demand and market share and; (b) since imports have generally been made under advance license, customs duty should not be added while determining price undercutting. Comparison of notional customs duty added landed price of import with rebated selling price of domestic

industry (wherein rebates have been granted to compensate for customs duty benefits), at the least, would be highly misleading.

- Causal link – The undisputed facts that (a) domestic industry follows a pricing policy wherein the prices are determined based on import prices; and (b) the domestic industry has been forced to resort to price reductions, that too frequently than normal, alone establishes causal link between dumping and injury.
- Inventories of the product under consideration with the domestic industry are alarmingly high. There is decline in export price from subject countries as is evident from the followings:

Export Price USD per KG

	July 2008	Aug 2008	Sept 2008	Oct 2008	Nov 2008	Dec 2008
China PR	2.02	2.02	2.10	2.28	2.09	1.78
Indonesia	2.28	2.17	2.17	2.18	2.24	2.05

- Further, the domestic industry has collected transaction wise information of imports in post POI (table below). It may be seen that there is further decline in prices from subject countries.

Jan-Mar 09	USD KG
China PR	1.57
Indonesia	1.79

- There is further decline in export price from subject countries in post POI. In fact, these are the orders booked at the end of POI and must therefore have been included in the questionnaire responses of the responding exporters.
- Increase in export price between 2007-08 and POI –there was increase in the raw material cost in POI over 2007-08, as would be seen from the table below. This led to increase in the export price.

Rs./kg	2007-08	POI	Change
--------	---------	-----	--------

Raw material	53.66	66.26	12.6
Import price			
China PR	107.09	94.13	-12.96
Indonesia	94.55	98.47	3.92

It would be seen that whereas raw material cost in POI increased by 23.48%, export price from China declined by 12.10%, which the same increased by just 4.14% in case of Indonesia.

- Requirement of causal link under the Rules – the interested parties seems to have been interpreting the Rules to mean that the sole cause of injury must be dumped imports. This is not, however, the requirement. Under the Rules, one of the principal causes of injury must be dumped imports. The fact that the domestic industry prices its product based on import prices and the fact that the domestic industry has been forced to resort to price revisions downwards, that too more frequently than the normal itself establishes that dumped imports are causing injury to the domestic industry.

10.2 Regarding issue related to deemed exports sales and significant discount offered by the domestic industry on such sales, domestic industry has stated as under:

- The domestic industry follows a well laid down pricing policy. The domestic industry declares and sells the product as per "price list". The prices are not negotiated for each sale transaction. The domestic industry does not follow a system of responding to trade enquiries, giving quotations, price negotiations, procurement and execution of order. The domestic industry declares a "price list" and thereafter sells the material on the basis of declared price list. Barring exceptional circumstances, all sales made by the company are as per the price list with little or no discretion to the operating level of marketing executives to modify the prices.
- The domestic industry's list price must be used for comparison of imported product price with the domestic industry price. In a situation where the company sells material to different customers at different prices, negotiating prices each time, which vary from customer to customer, it might be relevant and appropriate to determine weighted average selling price for the quantities sold over the relevant period. However, in a situation where the company sells its product at pre-determined, declared public price lists and where such price lists are declared after considering international prices, the price comparison between the imported and domestic product must be carried out on the basis of such price lists. Domestic industry reiterates that the selling prices do not vary with customers and therefore there is no necessity of determining weighted average selling price of the quantities sold in a particular period.

- The price is fixed in a scientific and transparent manner. The basis of fixation of price is the prevailing international price. Considering prevailing international prices and various factors, which must be accounted for the differences which exists in different countries (such as exchange rate, customs duties etc), the company decides its basic price.
- The company has termed certain category of sales as "deemed exports". They have no disagreement with the opposing interested parties that deemed exports should not form part of domestic sales. However, merely because the company has designated certain sales as deemed exports, these would not become deemed exports.
- Deemed exports have been defined under the Foreign Trade Policy. Essential ingredients of deemed export sales are the following:

"Following categories of supply of goods by main / sub-contractors are regarded as "Deemed Exports" under FTP, provided goods are manufactured in India:

(a) Supply of goods against Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA;

(b) Supply of goods to EOUs or STPs or EHTPs or BTPs;

(c) Supply of capital goods to holders of Authorisations under EPCG Scheme;

(d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies / Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies / Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty;

(e) Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies / Funds as notified by DEA, MoF under ICB, in accordance with procedures of those agencies / Funds, which bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;

(f) Supply of capital goods, including in unassembled/ disassembled condition, as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till stage of commercial production, and spares to extent of 10% of FOB value to fertilizer plants;

- (g) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the MoF, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty;
 - (h) Supply of goods to power projects and refineries not covered in (f) above;
 - (i) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers-manufacturers) provided said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by customs;
 - (j) Supply to projects funded by UN agencies; and
 - (k) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB."
- Since the Govt. of India considers deemed export sales as export sales and further since the injury assessment must be made for domestic sales, the opposing interested parties have rightly claimed that deemed export sales should not be included in the domestic sales.
 - The domestic sales made by the domestic industry do not qualify as deemed export sales, even though it is using the terminology deemed exports in the market place. In fact, the consumer claims export benefits on the exports they make and the domestic industry uses the nomenclature "deemed export" simply for the reason that the fibre has been consumed in a product, which has been exported. However, all export benefits have been taken by the consumers and not by the domestic industry. If these were deemed exports sales, the domestic industry would have been entitled for various benefits granted under Foreign Trade Policy.
 - It is therefore submitted that these sales are not deemed export sales as understood by opposing interested parties but domestic sales only. Therefore, the sales have been rightly included under the head "domestic sales".

I. Examination by the Authority

11. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties; including the domestic industry's contention that since no benefit has been obtained by them under the foreign trade policy for the so-called "deemed exports", such sales should be treated as domestic sales. However, these claims and counter claims would be cross-checked during the course of further investigation and spot verification.

11.1 The Authority has taken on board various submissions made by the interested parties and have undertaken the injury analysis as under:

11.2 Annexure II of AD Rules provides for objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in

domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

11.3 As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of AD Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

11.4 The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties.

Cumulative assessment

12. Since countries involved in the present investigation are more than one, the Authority has examined whether conditions for cumulative assessment are prima facie satisfied. The Authority observes that:

- i. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed;
- ii. The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
- iii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evident from the fact that the domestic product and imported product are like Article; imports from each of the subject countries are significant; goods produced by the Indian Producers and imported from subject countries are in direct competition; common parties are resorting to use of imported material and domestic material; Indian Producers/customers are using domestic material and imported material; the exporters from the subject countries and

the applicant have sold the same product in the same periods to the same set of customers, etc.

12.1 In view of the above, the Authority considers it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.

Demand and market share:-

13. Demand of the product in the Country has been assessed as the sum of domestic sales of the domestic producers and imports from all sources.

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	POI	April-June 08 - Annualized	POI - Annualized
Sales of domestic industry in MT	223,147	226,178	237,640	49,784	100,925	199,136	201,850
Indexed	100	101	106	89	90	89	90
Imports in India in MT	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,560	12,658
Indexed	100	3,415	3,450	3,812	6,382	3,812	6,382
Demand in MT	223,345	232,952	244,482	51,674	107,254	206,696	214,508
Indexed	100	104	109	93	96	93	96
Market Share							
Subject Countries	0.06%	1.34%	2.77%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
Other Country	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Domestic industry	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

13.1 It is noted that demand for the product under consideration was increasing till 2007-08. The same has however declined (on proportionate basis) during April-June 08 period and the period of investigation. It is also noted that whereas demand for the product under consideration has shown decline during the POI; import volumes have increased significantly (on proportionate basis). It has been contended by some interested parties that there is decline in demand of product in India and therefore, injury to the domestic industry, if any, is not from the alleged imports. The Authority, however, notes that impact of decline in demand should have resulted into decline in imports as well on proportionate basis. However, it is seen that the imports of the subject goods at dumped prices from the subject countries have apparently led to a situation where the demand for the product under consideration has declined and that of imports have increased significantly.

13.2 This effect of the increase in imports is visible in the market share of imports as well. The market share of dumped imports from subject countries is significantly higher during the POI.

Import volumes and market share

14. The imports of the subject goods and the market share are given in the following table:

	2005-06	2006-07	2007-08	April- June 08	POI	April-June 08 - Annualized	POI - Annualized
Imports from Subject Countries (in MT)	125	3,121	6,779	1,890	6,329	7,561	12,658
Imports from Other than Subject Countries (in MT)	73	3,653	62	-	-	-	-
Total Imports (in MT)	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,561	12,658
Dumped imports in relation to Indian production %	0.09%	2.74%	2.46%	3.27%	5.54%	3.27%	5.54%
Dumped imports in relation to demand in India %	0.06%	1.34%	2.77%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
Market Share in Demand							
Subject Countries	0.06%	1.34%	2.77%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
Other Country	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Domestic industry	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

14.1 It is seen that:-

- The imports have shown a significant increase in absolute terms.
- The imports have increased in relation to production and consumption in India.
- While the market shares of the subject countries have increased but that of the domestic industry has declined. It is thus evident that the impact of the imports on the domestic industry has been adverse.

Price effect of imports

15. It is seen from the following table that there is marginal negative price-undercutting. However, the domestic industry has stated that it fixes the prices of the subject goods in tandem with the landed value of the product under consideration and this comparison should be made after including the turnover discount in the net selling price that it gives to its customers which is evidently contingent upon the turnover achieved; and if this turnover discount is included in the average selling prices, the price undercutting would be significantly positive.

	China PR	Indonesia
CIF Import Price	94.13	95.39
Landed Price	98.89	100.21
Net Selling price of Domestic Industry	98.72	98.72
Price Undercutting	(0.17)	(1.49)
Price Undercutting %	-0.02%	-1.5%

15.1 Price effect of the dumped imports has been adverse on performance of domestic industry as is evident from the following:-

The Authority has further made comparison of cost of production and selling price of the domestic industry along with the landed price of imports, which is given in the following table:

Rs/Kg.	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	POI (July –December 2008)
Cost of Production	68.29	69.87	73.88	93.47	100.02
Trend indexed	100	102	108	137	146
Selling Price	73.91	85.79	103.59	110.65	98.72
Trend indexed	100	116	140	150	134

Landed Price from China PR	137.65	86.40	112.50	110.64	98.89
Trend indexed	100.00	63	82	80	73
Landed Price from Indonesia	77.08	87.39	99.33	107.62	100.21
Trend indexed	100	113	129	140	131

15.2 It is seen that while selling price of the domestic industry increased from 100 in base year to 134 during the POI. However, its cost of production increased from 100 in the base year to 146 during the POI. Apparently, the domestic industry could not increase its selling price in line with the increase in its cost of production; thereby indicating that the dumped imports are significantly suppressing the prices of the domestic industry.

15.3 The Authority has also examined price underselling of the domestic industry and notes that the landed value from subject countries is significantly below the non-injurious price of domestic industry as may be seen from the following table.

In RS./Kg.

	NIP	Landed price	Price Underselling	Price Underselling %
China PR	108.04	98.89	9.15	9.25
Indonesia	108.04	100.21	7.83	7.81

15.4 Apparently the domestic industry is forced to sell the subject goods below the non-injurious price

Economic parameters of the domestic industry

16. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin

of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:-

Sales volumes

17. The sales volume of domestic industry is given in the following table:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	POI	April-June 08 - Annualized	POI - Annualized
Sales volume	223,147	226,178	237,640	49,784	100,925	199,136	201,850
Trend indexed	100	101	106	89	90	89	90

17.1 It is noted that sales of domestic industry had increased up to 2007-08 and then declined during April-June 08 period and the POI. Though, there has been a decline in demand; however, with the decline in demand, the imports have not declined proportionately, but they have actually increased.

Capacity and Capacity Utilization

18. Information relating to capacity and capacity utilization is given in the following table:

	2005-06	2006-07	2007-08	April- June 08	POI	April-June 08 - Annualized	POI - Annualized
Capacity	257,325	266,450	266,450	82,425	166,935	329,700	333,870
Trend Indexed	100	104	104	128	130	128	130
Production	228,981	246,832	277,818	57,829	114,314	231,317	228,628
Trend Indexed	100	108	121	101	100	101	100
Capacity Utilization	88.99%	92.64%	104.27%	70.16%	68.48%	70.16%	68.48%
Trend Indexed	100	104	117	79	77	79	77

18.1 It is seen that production and capacity utilization of the domestic industry was improving till 2007-08, which declined during the April-June 08 period and the POI. It has been alleged by some interested parties that domestic industry had increased its capacity in March 2008 and a new capacity cannot perform at same level of old capacity. The Authority has examined performance of domestic industry on same capacity level, which was there before expansion and notes that even with same capacity levels, capacity utilization has declined from 104.27% in 2007-08 to 85.8% in the POI.

Profit/Loss, return on investment and cash profits

19. Information relating to profit/loss, return on investment and cash profits is given in the following table:-

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	POI	April-June 08 - Annualized	POI - Annualized
PBT Rs. Lacs	27,625.60	46,615.29	74,975.42	8,706.06	10,142.95	35,067.85	20,285.9
Trend Indexed	100	169	271	127	73	127	73
PBT Rs. KG	12.38	20.61	31.55	17.61	10.65	17.61	10.05
Trend Indexed	100	166	255	142	81	142	81
PBT Rs. Lacs	30,919.72	50,342.49	79,695.45	10,059.11	14,927.41	40,236.45	29,854.8
Trend Indexed	100	163	258	130	97	130	97
Cash Profit							
Rs. Lacs	31,082.54	50,703.30	79,342.94	10,169.03	13,054.51	40,676.13	26,109.0
Trend Indexed	100	163	255	131	84	131	84
ROI NFA Basis	37.54%	55.94%	64.32%	30.65%	21.26%	30.65%	21.26%
Trend Indexed	100	149	171	82	57	82	57
ROI GFA Basis	23.62%	35.19%	43.87%	22.20%	14.77%	22.20%	14.77%
Trend Indexed	100	149	186	94	63	94	63

19.1 The Authority notes that the profitability was improving till 2007-08, which declined thereafter significantly. The return on investment and the cash profits have followed the same trend as that of profitability. It is noted that though during the POI,

the average return on investment was positive, however, it declined significantly over the injury period. The Authority further examined profits and ROI situation of the domestic industry on quarterly basis within the POI. It is further noted that performance of domestic industry declined significantly in the 2nd quarter of POI, as may be seen from the following table:

	Jul-Sept 08	Oct-Dec 08	POI (July –December 2008)
ROI (considering capital employed on NFA basis)	28.38%	13.18%	21.26%
Trend Indexed	76	35	57
ROI (considering capital employed on GFA basis)	20.18%	9.23%	14.77%
Trend Indexed	85	39	68

Inventories:

20. Inventory levels of the domestic industry have been as under:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	POI (July – December 2008)
Inventory	13654	5236	8233	13587	13535
Inventory for no. of days sales	20	7	11	21	20

20.1 It is noted that inventory of the domestic industry declined in 2006-07, which again increased in 2007-08. The inventory further increased during April-June 08 period and the POI as compared to the 2007-08 period.

Employment, wages and productivity

21. Information relating to employment, wages and productivity of the domestic industry has been as under:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	POI (July –December 2008)
Employment	4,813	4,683	4,640	4,640	4,563
Trend Indexed	100	97	96	96	95
Employment per 1000 MT capacity	19	18	17	14	14
Trend Indexed	100	94	93	75	73
Productivity per day (MT)	654.23	705.23	793.77	660.91	653.22
Tend Indexed	100	108	121	101	100
Productivity per employee per annum (MT)	47.58	52.71	59.87	49.85	50.10
Trend Indexed	100	111	126	105	105

21.1 It is noted that employment level of the domestic industry declined over the injury period. The Authority, however, notes that this decline is not only seen in the POI, but was there even before the POI. The wages of the domestic industry shows normal increase. As regards productivity per employee, it increased till 2007-08 and showed a decline during April-June 08 period and the POI.

Dumping Margin:

22. It is observed that dumping margin in respect of exports from the subject countries is positive and more than the *de-minimis* limits prescribed.

Growth

23. The Authority notes that the growth of the domestic industry is negative in terms of volume parameters such as sales (declined by 10% from the base year and 15% from 2007-08), production (18% from 2007-08) and capacity utilization (declined by 23% from the base year and 34% from 2007-08). The growth in value parameters is also seen as negative. Profits (declined by 27% from the base year and 73% from 2007-08) of the domestic industry and the ROI (declined by 43% from the base year and 67% from 2007-08) too deteriorated significantly in POI.

Threat of material injury

24. The Authority notes that the rate of increase of dumped imports is significant, indicating the likelihood of substantially increased importation. There is a significant price undercutting and significant price suppression indicating potential increase in imports and having significant depressing effect on domestic prices. However, the claims regarding threat of material injury would be examined in detail during the course of the investigation.

Conclusion on material injury

25. It is seen that performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, return on investments, cash profit, production, sales and capacity utilization and market share. The Authority has also examined quarterly performance of domestic industry within the period of investigation. The deterioration is more pronounced in terms of quarterly performance in the 2nd quarter of the period of investigation. The examination of the above parameters shows that the domestic industry has apparently suffered material injury.

J. Causal Link

26. The Authority has examined whether other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It was found as follows: -

Imports from third countries.

26.1. The Authority has collected the transaction-wise imports data of the subject goods from DGCI&S. From the information available on record, the Authority notes that there are no imports of subject goods from any other country.

Contraction in demand:-

26.2. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant improvement till 2007-08, and then shows decline during the POI. However, as compared to the demand, the imports have increased significantly, which ordinarily should have declined with the decline in demand. The Authority has not found any significant change in the pattern of consumption. There is no evidence available on record that trade restrictive practices could have contributed to the injury to the domestic industry. The Applicant has claimed that there is no significant changes in technology, and none of the interested parties have disputed the claim of the Applicant. While the export volumes of the domestic industry have marginally declined as compared to the 2007-08 period; the price and profitability in the

domestic and export market have been analysed on a segregated basis. Therefore, the analysis on injury is not misrepresentative on account of export performance.

26.3. The Authority notes that the following parameters show that material injury to the domestic industry is due to dumped imports.

- The imports from subject countries have significantly increased over the injury period. It is noted that while the market share of the domestic industry has declined, that of the imports from the subject countries have increased.
- There is price underselling, resulting in a situation where the domestic industry is unable to increase its prices in proportion to the increase in the cost of production.
- The significant price-suppression caused by the dumped imports has adversely impacted the domestic industry, resulting in significant decline in profits and cash flow.

26.4 The Authority therefore, provisionally holds that material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.

K. Conclusions:

27. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:

- (a) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below associated Normal values.
- (b) The domestic industry has suffered material injury in respect of the product under consideration.
- (c) The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

L. Indian industry's interest & other issues

28. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way; and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

28.1 It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

M. Recommendations

29. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a preliminary investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having provisionally established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

29.1 Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of 'injury', so as to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, provisional antidumping duty as per amount specified in Col 8 of the table below is recommended to be imposed from the date of the notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries.

Sl. No	Heading / Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Cur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	M/s P T South Pacific Viscose	M/s P T South Pacific Viscose	0.127	Kg	US\$
2	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	PT. Indo Bharat Rayon	PT. Indo Bharat Rayon	0.217	Kg	US\$

3	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	Any combination other than as specified at Sr. No.1 & 2		0.760	Kg	US
4.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Any country other than Indonesia	Any	Any	0.760	Kg	US\$
5.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Any country other than attracting Anti-dumping duty	Indonesia	Any	Any	0.760	Kg	US\$
6.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	China PR	China PR	Any	Any	0.199	Kg	US\$
7.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	0.199	Kg	US\$
8..	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Any country other than attracting Anti-dumping duty	China PR	Any	Any	0.199	Kg	US\$

N. Further Procedure

30. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings: -

(a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;

(b) Exporters, importers, the applicant and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of the these Preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;

(c) The Authority would hold a hearing to hear the views of various interested parties orally;

(d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;

(e) The Authority would disclose essential facts as per the AD Rules before announcing final findings.

R. GOPALAN, Designated Authority